04 - देश में सबकुछ भारतीय होना चाहिए

05 - बाल श्रम और मौलिक अधिकारों का हनन

A Daily News Magazine

भोपाल

गुरुवार, 12 जून, 2025

06 - दो मंदिर, एक मदरसा और तीन पक्के मकानों पर चला बुलडोजर

07 - एम्स भोपाल के डेंटल विभाग के डॉ. अंशुल राय ने...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 273, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

दोहरे खेल का माहिर पाक छद्म युद्ध को दूसरा रूप दे सकता है

ले.जन. एच.एस. पनाग (रि.)

परमाणु शक्ति संपन्न दो देशों के बीच अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित लगभग पारंपरिक किस्म की टक्कर 'ऑपरेशन सिंदूर' से उठा गुबार अब थमने लगा है, इस सवाल पर घनघोर बहस छिड़ी हुई है कि आखिर जीता कौन? भारत और पाकिस्तान, दोनों ने अपनी जीत के दावे किए हैं।

अनुभव जनित ज्ञान यही कहता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से विनाशकारी युद्ध और निर्णायक जीत बीती बात हो गई है, खासकर परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच हुए युद्ध में। इसलिए, युद्धों और संघर्षों के नतीजे का आकलन मनोवैज्ञानिक पहलू से करना ही बुद्धिमानी की बात होगी। संबंधित देशों का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व तो नतीजे का हिसाब लेता ही है और इसी के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा की भावी रणनीति बनाई जाती है।

भारत का राजनीतिक मकसद थाः पाकिस्तान के अंदर खौफ पैदा करना। दूसरे शब्दों में, वह पाकिस्तान को मजबूर करना चाहता था कि वह आगे कभी भारत में जम्मू-कश्मीर या कहीं भी आतंकवाद के जरिए छद्मयुद्ध न छेड़ पाए। यह लक्ष्य एक तरह के सीमित युद्ध जैसे नियंत्रित सैन्य ऑपरेशन के जरिए हासिल किया जाना है। और इससे भी महत्वपूर्ण यह कि इसमें पाकिस्तान की परमाणु क्षमता का उल्लंघन न हो। इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है।

भारत का सैन्य लक्ष्य 'एक्शन-उसका जवाब-फिर एक्शन' वाला नियंत्रित, गतिशील सैन्य ऑपरेशन चलाना था जिसमें पाकिस्तान के जमीनी और हवाई क्षेत्रों का उल्लंघन न हो, और ऐसे हालात पैदा करके मनोवैज्ञानिक शिकस्त देना था जिसमें शत्रु के लिए जवाबी कार्रवाई असहनीय रूप से महंगी साबित हो। पाकिस्तान का राजनीतिक लक्ष्य भारत को पाकिस्तान पर ज़ोर-ज़बरदस्ती करने से रोकना और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना था। उसे उम्मीद थी कि ऐसा करते हुए वह भारत के साथ खुद को फिर से उलझा सकेगा और कश्मीर विवाद को अंतरराष्ट्रीय प्रचार दिला सकेगा। उसका सैन्य लक्ष्य अपनी सीमित अत्याधुनिक सैन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत के आक्रमणकारी कार्रवाइयों को परास्त करना था जिसके तहत उच्च क्षमता वाली जवाबी कार्रवाई करनी थी ताकि आगे के ऑपरेशन काफी महंगे साबित हों। भारत अंतरराष्ट्रीय दखल को रोकने पर डटा था, और पाकिस्तान का इरादा यह था कि अंतरराष्ट्रीय दखल जल्द-से-जल्द हो ताकि भारत को रोका जा सके।

ऐसे माहौल में जो पक्ष 'ओओडीए' (ऑब्जर्व-ओरिएंट-डिसाइड-एक्ट) का चक्र बार-बार और तेजी से पूरा कर सकता था वही रणनीति के मामले में मनोवैज्ञानिक लकवे की स्थिति पैदा कर सकता था, जिसमें दुश्मन संसाधन होने के बावजूद जवाबी कार्रवाई करने में नाकाम हो जाता है। लब्बोलुआब यह है कि थलसेना की हवाई सुरक्षा व्यवस्था और 'यूएएस' की सहायता से वायुसेना ने 'ओओडीए' वाले चक्र को तेजी से पूरा किया और रणनीति के मामले में मनोवैज्ञानिक लकवे की स्थिति पैदा करने में सफल रही। 10 मई की सुबह भारतीय वायुसेना ने पूरे पाकिस्तान में 11 विमान अड्डों/रडार तथा कमांड व कंट्रोल केंद्रों पर भारी हमले किए। पाकिस्तान ने अब बताया है कि इस ऑपरेशन में सात और अड्डों पर हमले किए गए थे।

भारत के राजनीतिक तथा सैन्य उद्देश्यों के तहत ये हमले जान-माल का नुकसान करने से ज्यादा, अपनी ताकत दिखाने के लिए किए गए। रणनीति के मामले में मनोवैज्ञानिक लकवे की ऐसी गंभीर स्थिति पैदा कर दी गई थी कि पाकिस्तानी वायुसेना और उसकी हवाई सुरक्षा व्यवस्था इस ऑपरेशन में कोई दखल तक नहीं दे पाई। पाकिस्तान का सैन्य तथा आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर भारतीय वायुसेना की रहम पर निर्भर हो गया था, इसलिए पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की मांग की।

याद रहे कि 16 दिसंबर 1971 को उसकी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में जब आत्मसमर्पण किया था तब वह लगभग साबुत थी। उस समय जीत रणनीति के मामले में मनोवैज्ञानिक पराजय देकर हासिल की गई थी। मैंने राजनीतिक और सैन्य लक्ष्यों के बारे में जो चर्चा की है वह सैन्य सिद्धांत पर आधारित है। घोषित राजनीतिक तथा सैन्य लक्ष्य आतंकवादियों और उनके रहनुमाओं (पाकिस्तानी सेना) को सजा देना था। अगर वास्तव में यही लक्ष्य था, तो यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि रणनीतिक नतीजा योजना के मुताबिक नहीं बल्कि संयोग से हासिल हो गया।

पाकिस्तान को रणनीति के मामले में मनोवैज्ञानिक रूप से पराजित करके मजबूर वाली स्थिति में ला दिया गया है। लेकिन यह स्थिति कब तक रहेगी, यह इस पर निर्भर करेगा कि भारत सैन्य टेक्नोलॉजी के मामले में भारी बढ़त कब तक बनाए रखता है, जो कि पाकिस्तान की पहुंच से बाहर है। चूंकि रणनीति के मामले में पाकिस्तान की मनोवैज्ञानिक हार के बावजूद उसकी परमाणु क्षमता ने उसकी रक्षा व्यवस्था को साबुत रखा है, इसलिए वह भारत को फिर चुनौती देने के लिए टेक्नोलॉजी के मामले में बढ़त लेने और अपनी ताकत बढ़ाने की हमेशा कोशिश करेगा। लेकिन उसकी बदहाल अर्थव्यवस्था इसमें रोड़ा बनेगी। 373 अरब डॉलर की अपनी जीडीपी के कारण उसकी यह हसरत एक सपना ही बनी रहेगी। चीन उसे मुफ्त में कुछ देने से रहा। पाकिस्तान अब आतंकवाद को अपनी नीति का साधन बनाने की रणनीति की गंभीर समीक्षा करेगा। लेकिन यहां यह बता देना उपयुक्त होगा कि आतंकवाद को एक अवधारणा के रूप में कभी खारिज नहीं किया गया है। पाकिस्तान दोहरा खेल खेलने में माहिर रहा है, जैसा उसने 2001 और 2021 में अमेरिका के साथ खेला था। यह भी हो सकता है कि आतंकवादी बगावत पर उतर आएं और मनमानी करने लगें। इसलिए, पाकिस्तान मामले को गरम रखने के लिए छद्म युद्ध को सावधानी से दूसरा रूप दे सकता है। वह फिर से स्थानीय आतंकवादियों पर ज्यादा भरोसा कर सकता है।

चीन लंबे समय तक भारत का प्रतिद्वंद्वी रहेगा और पाकिस्तान महज एक उकसावा बना रहेगा। भारत को अपनी सेना में तेजी से बदलाव लाने के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और उसके साथ राष्ट्रीय रक्षा नीति को औपचारिक रूप देना चाहिए। यह उस सैन्य रणनीति का रास्ता बनाएगा जो संघर्ष से जुड़े जिससे सभी तरह के खतरों का सामना किया जा सकेगा। जनसभाओं में नेतृत्व जिस राजनीतिक सुरक्षा सिद्धांत की बात करता है उसे तार्किक सुरक्षा रणनीति में बदलना होगा। कोई भी राष्ट्र गिनती के आतंकवादियों की हरकतों पर आधारित 'स्थायी संघर्ष' में उलझा नहीं रह सकता।लिए हमें अपने रक्षा बजट को जीडीपी के 4 फीसदी के बराबर करना होगा। चीन के दबाव और मिलीभगत से फिर जोश में आए पाकिस्तान के साथ एक और टक्कर हो सकती है। लेकिन भारत अगर पाकिस्तान को निर्णायक रूप से हराने और चीन को भी गतिरोध की स्थिति में डालने लायक सैन्य क्षमता हासिल कर लेता है तो अगले संघर्ष को रोका जा सकता है।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

प्रदेश में हर संभाग में खुलेंगे नए वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर : सीएम

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र और वन्यजीवों की विविधता से संपन्न राज्य है। भारत में सबसे अधिक बाघ (टाइगर) मध्यप्रदेश की धरती पर देखने को मिलते हैं। तेंदुआ (लेपर्ड) और गिद्ध (वल्चर) की संख्या भी मध्यप्रदेश में सबसे अधिक है। प्रदेश के अलग-अलग वन क्षेत्रों में मगरमच्छ और घड़ियालों का बसेरा है। प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण, जंगलों की रक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में वन्य प्राणी संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में तेज गति के साथ अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर स्थापित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को गुजरात रवाना होने के पहले मीडिया में जारी एक संदेश में यह विचार रखे।

संभाग स्तर पर आवश्यक हैं रेस्क्यू सेंटर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब वन्यजीव प्रेमियों के लिए मध्यप्रदेश में किंग कोबरा भी लेकर आए हैं। चीतों को पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर वन क्षेत्र में छोड़कर एक नया नेशनल पार्क विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक दो नए टाइगर नेशनल पार्क बनने और चीतों के साथ-साथ दूसरे वन्य जीवों की संख्या बढ़ने से संभाग स्तर पर रेस्क्यू सेंटर की आवश्यकता महसूस हो रही है। इन सेंटर्स की स्थापना के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में अब तक केवल एक रेस्क्यू सेंटर राजधानी भोपाल स्थित वन विहार में है। यहां प्रदेशभर से घायल और बीमार वन्यजीवों को इलाज के लिए लाया जाता है, लेकिन उनके अनुकूल वातावरण में बदलाव हो जाने के कारण कई बार परेशानियां आती हैं।

मध्यप्रदेश में जू की संख्या बढ़ेगी

राज्य सरकार प्रदेश में चिड़ियाघरों अर्थात प्राणी उद्यान (जू) की संख्या में भी वृद्धि करने जा रही है। बजट में दो प्राणी उद्यान की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुजरात में देश का सर्वश्रेष्ठ जू एवं रेस्क्यू सेंटर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि वे गुजरात की अध्ययन यात्रा में जामनगर में वन्यजीवों की देखरेख के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे साथ ही वन्यजीवों का आदान-प्रदान कर उनके जीवन रक्षा की संभावनाएं भी तलाशेंगे।

नागरिकों के साथ-साथ वन्यजीवों के प्रति भी संवेदनशील

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के कई विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में वेटनरी कोर्स और वेटनरी अस्पताल शुरू कर पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। निकट भविष्य में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। वन संपदा और वन्यजीवों के संरक्षण का भी व्यापक अभियान प्रदेश में चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया है कि अगर किसी वन्यजीव के संकट में होने की जानकारी मिले या दिखाई दे तो नज़दीकी फॉरेस्ट ऑफिसर को सूचित करें। प्रदेश सरकार अपने नागरिकों की चिंता करने के साथ-साथ वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भी संवेदनशील है।

कल मुख्यमंत्री श्रमिक परिवारों के खातों में संबल योजना की राशि करेंगे अंतरित

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संबल योजना अंतर्गत, अनुग्रह सहायता के 6821 प्रकरणों में 150 करोड़ रूपये सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। शुक्रवार को जबलपुर के बरगी में होने वाले इस कार्यक्रम में श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में संबल योजना, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। योजना अंतर्गत प्रारंभ से अब तक 1 करोड़ 76 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। पंजीयन प्रक्रिया निरंतर जारी है। योजना में अनुग्रह सहायता अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये प्रदान किये जाते हैं। स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये एवं आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपये तथा अंत्येष्टि सहायता के लिए 5 हजार रूपये प्रदान किये जाते हैं। संबल योजना में जहाँ एक ओर महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता के लिये 16 हजार रुपये दिये जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर श्रमिकों के बच्चों को महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना में उच्च शिक्षा के लिये सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

सुप्रभात

मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है
ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है

बस अपने वास्ते ही फ़िक्रमंद हैं सब लोग
यहां किसी को किसी का ख़याल थोड़ी है

परों को काट दिया है उड़ान से पहले
ये ख़ौफ़ ए हिज्र है शौक़ ए विसाल थोड़ी है

मज़ा तो तब है कि हम हार के भी हंसते रहें
हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है

लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले
गुरूब होने का मतलब ज़वाल थोड़ी है।

- परवीन शाकिर

सोनम ने ही रची थी पति की हत्या की साजिश

● पुलिस के सामने किया कबूल, सबूत देखकर रो पड़ी

मेघालय के चर्चित हनीमून हत्याकांड में बड़ा खुलासा

शिलांग/इंदौर (एजेंसी)। मेघालय में हुए चर्चित हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ के दौरान सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। सूत्रों के मुताबिक, शिलांग में पुलिस ने जब वारदात से जुड़े पुख्ता सबूत सोनम के सामने रखे तो वह फूट-फूटकर रो पड़ी। इसके बाद उसने जुर्म स्वीकार कर लिया। मेघालय पुलिस ने पूछताछ के दौरान सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का आमना-सामना कराया। उसे पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि मेघालय पुलिस की एसआईटी राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच कर रही है। अब मेघालय पुलिस पूरे क्राइम सीन को रीक्रिएट करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को घटनास्थल से कुछ डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सऐप चैट्स भी मिले हैं, जो हत्या की साजिश को सिद्ध करते हैं। गौरतलब है कि राजा और सोनम रघुवंशी हनीमून मनाने मेघालय गए थे।

● **सोनम ने गलती की, उसे सजा-ए-मौत मिले-** इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पत्नी सोनम समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने शिलॉन्ग कोर्ट में पेश किया है। उधर, इंदौर में सोनम का भाई गोविंद अचानक राजा के परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा। गोविंद ने राजा की मां और भाई से मुलाकात की। मां के गले लगकर रोया भी। गोविंद ने कहा कि आरोपी राज कुशवाह और सोनम के बीच अफेयर नहीं था। वह राज को राखी बांधती थी। राजा के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। राजा के भाई विपिन ने बताया कि गोविंद घर आया था, उसने माफी मांगी। बोला- मम्मी जी मेरी बहन ने गलती की है। सोनम ने जो गलती की है, उसके लिए उसे सजा-ए-मौत होनी चाहिए।

वेटिंग टिकट कन्फर्म हुआ या नहीं, 24-घंटे पहले पता चलेगा

● अभी 4 घंटे पहले चार्ट बनने पर पता चलता है, देशभर में जल्द लागू होगा नियम

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर्स के लिए नए नियम लेकर आई है। अब यात्रियों को सीट कन्फर्म हुई या नहीं इसकी जानकारी ट्रेन निकलने के एक दिन पहले पता चल जाएगी। रेलवे ने अब चार्ट बनाने का समय ट्रेन के चलने से 24 घंटे पहले कर दिया है। अभी सिर्फ 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट बनाया जाता था। ऐसे में वेटिंग टिकट वालों को आखिरी वक्त तक कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नियम 6 जून से बीकानेर डिवीजन में लागू किया गया है। धीरे-धीरे इसे देशभर के अन्य डिवीजनों में भी लागू किया जाएगा। रेलवे ने यह भी कहा कि नए नियम से तत्काल टिकट बुकिंग या अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। तत्काल टिकट यात्रा से एक दिन पहले बुक किए जाएंगे और उनकी कंफर्मेशन प्रक्रिया पहले के जैसे ही रहेगी। इससे पहले भारतीय रेलवे ने 1 मई से वेटिंग टिकट के लिए नए नियम लागू किए थे।

● **कन्फर्म न होने पर टिकट अपने-आप रद्द हो जाएंगे-** रेलवे ने बताया कि आईआरसीटीसी के जरिए बुक किए गए टिकट कन्फर्म न होने पर अपने आप रद्द हो जाते हैं, लेकिन काउंटर से बुक किए गए टिकट का इस्तेमाल लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए करते हैं। इस वजह से कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को असुविधा होती है। 1 मई, 2025 से लागू होने वाला एक और नियम यह है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से बुक की जाने वाली हर ट्रेन टिकट के लिए आधार-आधारित मोबाइल सत्यापन की आवश्यकता होगी। इस उपाय का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना और बुकिंग प्रणाली के दुरुपयोग को रोकना है। 21 मई को भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट टिकट से जुड़े ऑटो अपग्रेड प्रक्रिया में बदलाव किए थे।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 38 °c | न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ गुरुवार, 12 जून 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

मणिपुर में सुरक्षाकर्मियों पर गोली चलाने का आरोपी गिरफ्तार

हिंसा के 19 आरोपी भी हिरासत में

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर में 9 जून को हुए प्रदर्शन में सुरक्षाकर्मियों पर गोली चलाने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बुधवार को बताया कि एक मैतेई ग्रुप के एक सदस्य बोइनाओ पंगेइजम (39 साल) को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। वह अरम्बाई टेंगोल का सदस्य है। बोइनाओ समेत कुछ अन्य प्रदर्शनकारी इम्फाल पश्चिम जिले में सड़क जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे सुरक्षाकर्मियों पर गोली चलाकर भागे थे। मजिस्ट्रेट ने उसे आठ दिनों की पुलिस

हिरासत में भेजा है। इसके अलावा इम्फाल पूर्वी जिले में हिंसा के आरोप में 19 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। मैतेई नेता अशेम कनन सिंह की 7 जून को को गिरफ्तारी के बाद राज्य में हिंसा भड़क गई थी। इंफाल के कई इलाकों में गाड़ियां जला दी गईं, सड़कों पर टायर और पुराने फर्नीचर भी जलाए थे। पुलिस से झड़प के अलावा प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की भी कोशिश की थी। 3 मई, 2023 को कुकी-मैतेई के बीच जातीय हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1500 से ज्यादा घायल हुए। 70 हजार से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। हिंसा मामलों में 6 हजार से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। मैतेई नेता अशेम कनन सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वह मणिपुर पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल था।

मैंने ऐसा पीएम नहीं देखा वोट के लिए गरीबों-युवाओं को मूर्ख बनाते हैं

- कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले-पीएम मोदी ने 11 साल में 33 गलतियां की

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। खड़गे ने बुधवार को कहा कि बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33 गलतियां की हैं। मैं 65 साल से राजनीति में हूं, लेकिन उनके जैसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। खड़गे ने कहा, हम झूठ बोलते हैं, गलतियां करते हैं, वोट लेने के लिए युवाओं और गरीबों को मूर्ख बनाते हैं। जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तो कभी जवाब नहीं देते। वे अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करते हैं। वे सिर्फ बोलते रहते हैं। बता दें कि

नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। मोदी सरकार ने बीते सोमवार को अपने तीसरे कार्यकाल की पहली और कुल मिलाकर 11वीं सालगिरह मनाई। मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने इससे पहले 9 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए मोदी सरकार के 11 सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए थे। उन्होंने लिखा था, सामाजिक ताने-बाने को गहरा आघात पहुंचाया है।

सिंधु नदी के नए प्रोजेक्ट्स में स्टोरेज पर रहेगा फोकस

भारत ने बना लिया खास प्लान, उधर पानी को लेकर गिड़गिड़ा रहा पाक

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को बताया कि सरकार जम्मू-कश्मीर में उन जलविद्युत परियोजनाओं के लिए अधिक जल भंडारण की योजना बना रही है, जो अभी शुरुआती चरण में हैं। हालांकि, जो परियोजनाएं पहले से पाइपलाइन में हैं, उनके तकनीकी विवरण तय हो चुके हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एक प्रेस वार्ता में मंत्री ने कहा, जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, जो परियोजनाएं पहले से पाइपलाइन में हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि उनके तकनीकी बिंदु पहले ही तय हो चुके हैं। लेकिन कुछ योजनाएं अभी शुरुआती स्तर पर हैं, जिनमें अधिक जल भंडारण और बिजली उत्पादन की

योजना बनाई जा सकती है। यह निर्णय 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया, जिसमें 26 नागरिकों की जान गई थी। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच छह नदियों- सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के जल के उपयोग और वितरण को नियंत्रित करती है। इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली में बड़े जल भंडारण वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर प्रतिबंध है। अब सरकार नए प्रोजेक्ट्स में भंडारण क्षमता बढ़ाने की संभावना पर विचार कर रही है।

- **चिनाब पर तेजी से बन रहीं चार प्रमुख परियोजनाएं-** केंद्र सरकार चिनाब नदी पर चार प्रमुख परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना चाहती है। ये परियोजनाएं- पाकल दुल (1,000 मेगावाट), रैतल (850 मेगावाट), किरू (624 मेगावाट) और क्वार (540 मेगावाट) हैं। पाकल दुल जम्मू-कश्मीर में बन रही पहली स्टोरेज-बेस्ड हाइड्रो परियोजना है, जिसकी 109 मिलियन क्यूबिक मीटर की जल भंडारण क्षमता होगी और इसके सितंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। पहलगाम हमले के बाद औपचारिक रूप से पाकिस्तान को संधि को निलंबित करने का निर्णय सूचित किया था। इसके जवाब में, पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को चार बार पत्र लिखकर संधि को बहाल करने की अपील की।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साइबर हमलों से निपटने का दावा

प्रेस वार्ता में ऊर्जा मंत्री ने बताया कि हाल ही में चले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के ऊर्जा क्षेत्र पर बड़ी संख्या में साइबर हमले हुए, लेकिन सभी हमलों को पहले से लगे फायरवॉल्स की मदद से निष्क्रिय कर दिया गया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ी संख्या में सिस्टम पर साइबर हमले हुए। लेकिन हमने हर हमले का मुकाबला किया और कोई नुकसान नहीं होने दिया।

बिहार चुनाव से पहले 'यंग ब्लड' ने बढ़ा दी है टेंशन

नीतिश कुमार के लिए मुश्किल होगा युवाओं से पार पाना

पटना (एजेंसी)। बिहार चुनाव से पहले एक पुराना मुद्दा नीतिश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को परेशान करने लगा है। 5 जून को, कई छात्र

संगठनों के एक संयुक्त संगठन, बिहार छात्र संघ ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय आरक्षण की मांग को लेकर पटना में विरोध प्रदर्शन किया। नीति आयोग के नवीनतम अनुमानों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 3.9 फीसदी है, जो राष्ट्रीय औसत 3.2 फीसदी से अधिक है। राज्य में बहुत से युवा सरकारी नौकरियों पर निर्भर हैं, जो हाल के दिनों में अनियमितताओं से ग्रसित रही हैं। इसलिए, नौकरियां राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा हैं, जो चुनावों से पहले गूंज रहा है। डोमिसाइल आरक्षण की मांग करने वालों का तर्क है कि राज्य के बाहर से आए उम्मीदवार बिहार के युवाओं की नौकरियां छीन रहे हैं। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उनका नारा वोट दे बिहारी, नौकरी ले बाहरी तेजी से जोर पकड़ रहा है। डोमिसाइल आरक्षण के अंतर्गत, किसी विशेष राज्य की सरकार अपने निवासियों के लिए सरकारी नौकरियों या शैक्षणिक सीटों का एक हिस्सा आरक्षित करती है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना है।

बेंगलुरु भगदड़ की पूरी जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड और आरसीबी की

बेंगलुरु (एजेंसी)। बेंगलुरु में हुई भगदड़ के लिए कर्नाटक सरकार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को जिम्मेदार ठहराया है। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि इस इवेंट के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी और आयोजकों ने सोशल मीडिया के जरिए 'पूरी दुनिया' को इस इवेंट में शामिल होने बुला लिया। हाईकोर्ट में आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले और चार अन्य लोगों की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है। सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। सोसले ने 10 जून को कोर्ट में दलील दी थी कि पुलिस अधिकारियों को सिर्फसस्पेंड किया गया है, वे अरेस्ट नहीं हुए। सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों किया। 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की विक्ट्री परेड में मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। 33 घायल हो गए थे। यहां 3 से 4 लाख क्रिकेट फैंस खिलाड़ियों को देखने आए थे, जो स्टेडियम की क्षमता से कहीं ज्यादा थे। राज्य सरकार की तरफ से शशि किरण शेट्टी पेश हुए।

सीओ अनुज चौधरी के बाद अब 'संभल' से विदा हुई वंदना मिश्रा

- डीएम डॉ. राजेन्द्र पेंसिया ने एसडीएम का भी कर दिया तबादला

संभल (एजेंसी)। यूपी के संभल में एक बार फिर प्रशासनिक सुधार के लिए डीएम डॉ.राजेन्द्र पेंसिया ने एसडीएम वंदना मिश्रा का ट्रांसफर कर दिया है। यहां बीते साल 24 नंवबर को हुई हिंसा के वक्त से तैनात ज्यादातर अफसरों के तबादला कर नए अधिकारियों को नियुक्त किया जा चुका है। हिंसा के समय में सीओ अनुज चौधरी, वंदना मिश्रा,एएसपी श्रीश चंद्र कानून व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए यहां काफी चर्चित रहे थे। वहीं संभल जनपद में प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ बनाने के उद्देश्य से जिलाधकारी ने बड़े स्तर पर अफसरों के तबादले के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में फेरबदल करते हुए संभल व गुन्नौर तहसीलों के एसडीएम के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है।

केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में दो मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी

- 6405 करोड़ लागत,झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को करेंगे कवर

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि मीटिंग में झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करने वाले दो मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।

इन प्रोजेक्ट में 133 किमी वाले कोडरमा-बरकाकाना और 185 किमी वाले बल्लारी-चिकजाजुर का डुअल लाइन करना शामिल है। जिनकी लागत 6405 करोड़ है। इससे पहले 28 मई को हुई मीटिंग में डेवलपमेंट से जुड़े 5 फैसले लिए गए थे। केंद्र सरकार ने 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) बढ़ाई थी। साथ ही केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने का फैसला किया था। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे की दो मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी।

आंध्र प्रदेश में बदवेल-नेल्लोर के बीच 108 किमी लंबे फोर-लेन

हाईवे परियोजना को भी मंजूरी दी गई थी। 28 मई को केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई। धान की नई एमएसपी 2,369 रुपए तय की गई, जो पिछली एमएसपी से 69 रुपए ज्यादा है। कपास की नई एमएसपी 7,710 रुपए तय की गई। इसकी एक दूसरी किस्म की नई एमएसपी 8,110 रुपए की गई, जो पहले से 589 रुपए ज्यादा है। पिछली कैबिनेट मीटिंग 14 मई को हुई थी। उस मीटिंग में देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई थी। यह यूनिट 3706 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश के जेवर में लगाई जाएगी। टाटा और फॉक्सकॉन मिलकर इस यूनिट को बनाएंगे। प्लांट में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमाबाइल्स, पर्सनल कम्प्यूटर, और दूसरे डिस्प्ले डिवाइसेज के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनेंगे। हर महीने 3.6 करोड़ चिप बनेंगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2022 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत अब तक 6 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए

- सीजेआई गवई ने 'न्यायिक आतंकवाद को लेकर दे दी यह चेतावनी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने संविधान को स्याही में लिखी एक शांत क्रांति बताया है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी ताकत है जो न केवल अधिकार देती है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से दबे हुए लोगों को ऊपर उठाती है। वे ऑक्सफोर्ड यूनियन में फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन टू रियलाइजेशन एम्बॉडिंग द कॉस्टिट्यूशनंस प्रॉमिस विषय पर बोल रहे थे। इस दौरान सीजेआई गवई ने न्यायिक सक्रियता से न्यायिक आतंकवाद की ओर बढ़ने को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। दरअसल, बार एंड बेंच ने सीजेआई बीआर गवई से एक सवाल पूछा। सवाल था कि भारत में न्यायिक सक्रियता कितनी सही है।

ट्रंप की नीतियों के खिलाफ फूट पड़ा 'इमिग्रेशन' बम

- अमरीका के 12 राज्यों के 25 शहरों में तक पहुंची आग

लॉस एंजिलिस (एजेंसी)। अमेरिका के लॉस एंजिलिस में 5 दिनों से जारी प्रदर्शन के कारण शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। लॉस एंजिलिस की मेयर कैरन बैस ने इमरजेंसी की घोषणा की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के फैसले के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन अमेरिका के 12 राज्यों के 25 शहरों तक फैल चुका है। सैन फ्रांसिस्को, डलास, ऑस्टिन, टेक्सास और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात पर काबू पाने के लिए ट्रम्प ने लॉस एंजिलिस में 4 हजार नेशनल गार्ड के अलावा 700 मरीन कमांडो को भी तैनात

कर दिया है। उन्होंने कहा कि हालात खराब हो रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वे पूरी ताकत से निपटेंगे। लॉस एंजिलिस पुलिस ने करीब 1100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया।

पीएम से मिलने वाले मंत्रियों को करवाना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट

- देश में कोरोना के ऐक्टिव केस 7000 पार,74 मौतें; रोज 350+नए मामले

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में कोरोनावायरस के केसों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले सभी मंत्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। देशभर में कोरोना के ऐक्टिव केसों की संख्या 7121 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2223 केस हैं। इसके बाद गुजरात में 1223, दिल्ली में 757 और पश्चिम बंगाल में 747 पॉजीटिव मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, कोरोना के नए वैरिएंट से 74 मौतें हुई हैं। मंगलवार को 6 लोगों ने जान गंवाई।

जल रहा है 'जून', सड़कों पर बरस रही है आग

- सात दिन में देश का टेंपरेचर 8 से 13 डिग्री बढ़ा
- एमपी-राजस्थान समेत 6 राज्यों में लू का है अलर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। पिछले सात दिन में देशभर के तापमान में 8 से 13 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हुआ है। मंगलवार को पंजाब का बठिंडा 47.6 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म रहा। वहीं, हरियाणा के सिरसा में मंगलवार को पारा 46.2 डिग्री दर्ज किया गया।

राजस्थान में भी गर्मी और हीटवेव का तेज असर जारी है। मंगलवार को राजस्थान के 3 शहरों का तापमान 46 डिग्री या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में 47.4 डिग्री, कोटा में 46.3 डिग्री और बीकानेर में पारा 46 डिग्री दर्ज किया गया। देश के उत्तरी राज्यों- राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में दो दिन लू का अलर्ट है। दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री दर्ज किया गया, लेकिन गर्मी 47 डिग्री जैसी महसूस की गई। बुधवार को दिल्ली का तापमान 45 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है।

इधर, केरल में फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। केरल के उत्तरी

जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, 13 जून को 4 और 14 जून को 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मध्यप्रदेश में जून में सूरज के तीखे तेवर हैं। पिछले 3 दिन से नौतपा जैसी गर्मी है। मंगलवार को 28 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार रहा, जबकि नौगांव में सबसे ज्यादा 46.1 डिग्री पहुंच गया।

नर्मदापुरम, गुना, खजुराहो, टीकमगढ़ और सागर में तापमान 45 डिग्री या इससे अधिक रहा। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 2 दिन लू और तेज गर्मी का अलर्ट है। यूपी भीषण लू की चपेट में है। आज 17 जिलों में हीटवेव का अलर्ट है। पिछले 24 घंटे में 45.2 डिग्री तापमान के साथ झांसी सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर आगरा रहा, जहां पारा 45.1 डिग्री था।

वहीं, पूर्वी यूपी में मौसम बदलाव के संकेत हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, 11 से 12 जून के बीच पूर्वांचल के जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। राजस्थान में गर्मी और लू ने हालात खराब कर दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो राज्य में अगले 4 दिन गर्मी से राहत की संभावना नहीं है।

लक्ष्य को समय सीमा से पहले पूरा करने का भाव जरूरी : राज्यपाल

सिकल सेल मिशन के कार्य मानवता की सेवा का माध्यम

राजभवन में सिकल सेल समीक्षा बैठक हुई

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन के लिए संवेदनशीलता, सहानुभूति के साथ रोग उन्मूलन की प्रतिबद्धता जरूरी है। कार्य का भाव लक्ष्य को समय सीमा से पूर्व पूरा करने का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिकल सेल मिशन के कार्य मानवता की सेवा के माध्यम है। ईश्वरीय कृपा के भागी होने का यह बड़ा अवसर है। राज्यपाल श्री पटेल राजभवन में सिकल सेल मिशन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक में उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा श्री राजेन्द्र शुक्ल, आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित थे। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग के द्वारा सिकल सेल उपचार, प्रबंधन और नियंत्रण प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। उनको बताया गया कि

मिशन के अंतर्गत 19 जून से 3 जुलाई तक समस्त ग्राम पंचायतों, एकलव्य आवासीय स्कूलों एवं छात्रावासों में मेगा शिविर आयोजित होंगे। अधिक से अधिक स्क्रीनिंग जांच की जाएगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से लेकर जिला चिकित्सालयों में पीओसी किट के द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रतिदिन स्क्रीनिंग जांच का डेटा पोर्टल में दर्ज होगा। जेनेटिक काउंसलिंग की जाएगी। जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्रदान किए जाएंगे। ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर चिह्नित सिकल सेल रोगियों के लिए शिविर लगेंगे। उन्हें विशेषज्ञों की परामर्श सेवायें उपलब्ध कराई जाएगी। सिकल सेल रोगियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यू.डी.आई.डी. कार्ड प्रदान कर पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। आयुष विभाग द्वारा बताया गया कि विश्व सिकल सेल दिवस के तारतम्य में जनजातीय बहुल 20 जिलों में संचालित 78 आयुष औषधालयों में शिविर का आयोजन किया जाएगा।

सिकल सेल उपचार में सहायक आयुर्वेद दवाओं की किट का वितरण होगा। रोग उपचार में सहायक स्थानीय वनस्पति के संरक्षण, संवर्धन के प्रति जन जागरूकता के कार्य होंगे। सिकल सेल एनीमिया प्रभावित प्रत्येक ग्राम में जनजागृति के लिए प्रभात फेरी, योगाभ्यास, ग्राम-सभा आदि के आयोजन किए जाएंगे। बैठक में जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री दीपक खांडेकर, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, राज्यपाल के अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव, सचिव जनजातीय प्रकोष्ठ श्रीमती जमुना भिड़े, संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सुश्री सलोनी सिडाना, आयुक्त आयुष श्री संजय मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया

फ्रिज-ऐसी डिलीवरी के बाद बिन पैसा दिए भाग जाते थे आरोपी

भोपाल (नप्र)। कोहेफिजा थाना पुलिस ने दो शातिर ठग गिरफ्तार किए हैं। आरोपी ऐसी-टीवी और फ्रिज बुक करते थे। सामान की डिलीवरी लेने के बाद बिना पैसा दिए भाग जाते थे। पुलिस ने दोनों को मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से बोल्टाज कंपनी के तीन एसी, 2 वेयरपूल कंपनी का एक फ्रिज, जीईएम कंपनी की 2 फ्रिज करोमा कंपनी की एक टीवी, इन्डूयसायर कंपनी का एक कूलर सहित घटना में प्रयुक्त दो बाइक जब्त की गई हैं। जब्त सामान की कुल कीमत करीब तीन लाख रुपए बताई जा रही है।

फोन पर दिया था सामान का ऑर्डर: एसीपी अनिल बाजपेयी ने बताया कि 27 मई 2025 को फरियादिया सीमा ठाकरे ने कोहेफिजा थाना आकर बताया कि अज्ञात आरोपी द्वारा फोन के माध्यम से उसकी दुकान से 3 फ्रिज, 1 कूलर ,1 एलईडी टीवी बुक की। इसके बाद चिनार पैलेश कोहेफिजा तक डिलीवरी देने बुलाया। सामान लेने के बाद बिना पैसे दिए आरोपी भाग निकले। उनकी शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी।

इसी तरह की थी दूसरी वारदात: संजय दुबे ने थाने आकर बताया कि अज्ञात आरोपी ने फोन से उसकी दुकान से वोल्टाज कंपनी का एक 1.5 टन का एसी बुक किया और गुलमोहर हाईट्स कोहेफिजा से बिना पैसे दिए लेकर चले गए। संजय की शिकायत पर पुलिस ने दूसरी एफआईआर दर्ज की थी। दोनों मामलों की जांच के दौरान पुलिस ने दुकानों के कर्मचारियों की सीडीआर निकाली। इसी के साथ मुखबिरों को भी सक्रिय किया। जिसके बाद तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

गिरफ्त में आए शातिर ठग: आरिफ उर्फ नदीम पिता स्व. मोहम्मद खलील (25) निवासी मकान नंबर 1/3, मंगलवारा रोड छावनी दसवीं कक्षा तक पढ़ा है और फिलहाल बेरोजगार है। कैफ खान पिता स्व. मुसाहिद खान (19) निवासी मकान नंबर 335, गली नंबर 08, आरिफ नगर आठवीं कक्षा तक पढ़ा है और बेरोजगार है।

30 पंचायत सचिवों का ट्रांसफर

- सालों से एक ही पंचायत में जमे थे ; प्रभारी मंत्री की लगी मुहर

भोपाल (नप्र)। भोपाल जिला पंचायत के 30 सचिवों का तबादला किया गया हैं। इनमें से कई ऐसे हैं, जो सालों से एक ही ग्राम पंचायत में जमे थे। वहीं, कुछ के घर और ससुराल उन्हीं की ग्राम पंचायत क्षेत्र में थे। सीईओ ईला तिवारी ने मंगलवार देर रात ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए। इससे पहले जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप ने लिस्ट को मंजूरी दी। क्राइटेरिया के साथ ही जनप्रतिनिधियों की पसंद का ध्यान भी रखा गया। इसके बाद लिस्ट जारी की गई। हालांकि, अभी भी कई सचिव ट्रांसफर के दायरे में आ रहे हैं। उनकी लिस्ट भी तैयार हो रही है। 17 जून से पहले इन्हें भी जिले में एक पंचायत से दूसरी पंचायत में किया जाएगा। भोपाल में कुल 222 ग्राम पंचायतें हैं। वहीं, दो जनपदें बैरसिया और फंदा है।

35 की महिला ने बुजुर्ग को प्रेम जाल में फंसाया

- निकाह करने के बाद कार नाम कराई, रकम ऐंठी और बुजुर्ग को घर से निकाल दिया

भोपाल (नप्र)। भोपाल की एक 35 साल की महिला ने 74 साल के बुजुर्ग को प्रेम जाल में फांस लिया। महिला ने स्वयं को गैर शादीशुदा बताया था। वृद्ध से शादी करने के बाद महिला उन्हें गुना से भोपाल ले आई। यहां उनकी कार को अपने नाम कराया। उनकी लाख रुपए की कैश रकम को भी हड़प लिया। जब पीड़ित ने महिला को बताया कि उसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं तो महिला ने उन्हें घर से निकाल दिया। वारदात को दो साल के भीतर अंजाम दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी है। निशातपुरा पुलिस ने बताया कि 74 वर्षीय रफीक अहमद गुना जिले के रहने वाले हैं। दो साल पहले वे रुबीना बी (परिवर्तित नाम) नाम की महिला के संपर्क में आए थे। रुबीना से एक महिला रिश्तेदार के यहां पहचान हुई था। रफीक की पत्नी नहीं थी तथा वे अकेले थे जबकि उनके पास लाखों रुपए की संपत्ति थी।

गैर शादीशुदा बताकर किया निकाह: महिला ने खुद को गैर शादीशुदा बताते हुए नजदीकियां बढ़ाई तथा निकाह करने के लिए तैयार कर लिया। 35 साल की होने के बाद रुबीना ने 74 साल के रफीक अहमद से शादी की तैयारी की तथा उन्हें गुना से भोपाल लेकर आ गई। यहां पर दोनों हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी करोंद में रहने लगे। यहां पर महिला ने बुजुर्ग से निकाह भी कर लिया।

दो साल के भीतर संपत्ति हड़प ली: दो साल के भीतर महिला ने बुजुर्ग की कार अपने नाम पर करा ली। साथ ही 25 लाख रुपए से अधिक की नगदी व सामान ऐंठ लिया। पिछले दिनों जब बुजुर्ग के पास पैसे खत्म हो गए तो महिला ने बुजुर्ग को घर से निकाल दिया। इसी दौरान बुजुर्ग को यह भी पता चला कि महिला पहले से ही शादीशुदा है। बुजुर्ग ने मामले की शिकायत पुलिस से की।

किन्नर ने फांसी लगाकर किया सुसाइड

- झालावाड़ से नौकरी का बोलकर भोपाल आया था ; कमरे में मिली चार दिन पुरानी बॉडी

भोपाल (नप्र)। भोपाल के छोला मंदिर इलाके में रहने वाले किन्नर ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। वह झालावाड़ से भोपाल के ब्यूटीपार्लर में नौकरी करने का बोलकर आया था। एक साल से भानपुर मल्टी में किराए से रहा था। उसकी मौत के बाद बड़ी संख्या में किन्नर मॉर्चुरी रूम पहुंचे। उन्होंने घर वालों की मौजूदगी में खुलासा किया कि युवक पूरी तरह से किन्नर बन चुका था और उनकी टोली के साथ काम करता था। हालांकि परिजनों का कहना है कि मृतक गांव में लड़का बनकर ही रहता था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। एसआई महेश सरयाम ने बताया कि झालावाड़ का रहने वाला राहुल उर्फ राखी (24) पुत्र रामगोपाल माली छोला की भानपुर मल्टी में किराए से रह रहा था। एक साल पहले घर पर ब्यूटी पार्लर में नौकरी का बोलकर भोपाल आया था। यहां किन्नरों की एक टोली के साथ मिलकर मांगने का काम करने लगा था। उन्हीं के साथ रहता था।

भाई से की थी आखिरी बात: 7 जून को आखिरी बार उसने भाई बजरंग से कॉल पर बात की थी। इसके बाद से ही परिजनों से संपर्क नहीं किया। दो दिनों तक लगातार गेट नहीं खोला तब पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गेट तोड़कर शव निकाला।

सर्वेक्षण गुणात्मक एवं प्रमाणिकता के साथ करें : उप मुख्यमंत्री देवड़ा

सर्वेक्षण 3 माह की तय समय में पूरा करें : राज्यमंत्री श्रीमती गौर

- विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु समुदाय के सर्वेक्षण पर कार्यशाला हुई

भोपाल(नप्र)। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इन जातियों के कल्याण की गतिविधियों को पावन कार्य बताते हुए कहा कि यह गर्व करने योग्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिये इन समुदायों का सर्वेक्षण के माध्यम से डाटा इकट्ठा किया जायेगा। इस डाटा के आधार पर कार्यक्रम बनाये जायेगें और राज्य एवं केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से इन समुदायों को लाभांवित किया जायेगा। राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान में उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु समुदाय के सर्वेक्षण-2025 पर बुधवार को हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि जन अभियान परिषद और विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु कल्याण विभाग के बीच सर्वेक्षण के लिये एमओयू हुआ है। सर्वेक्षण प्रमाणिकता के साथ होगा। उन्होंने कहा कि सर्वे कार्य में लगे कार्य समन्वयक पूरी ईमानदारी एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि घुमन्तु समाज के उत्थान का यह पुण्य एवं पवित्र कार्य है। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु कल्याण विभाग के कार्य की सराहना भी की। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु समुदायों के परिवारों के समेकित विकास के दृष्टिगत सर्वेक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में प्रदेश के 12 जिलों में सर्वेक्षण का कार्य होगा और यह कार्य तय समय सीमा 3 माह में पूरा किया जायेगा। सितम्बर में सर्वेक्षण का प्रथम चरण पूरा होने के बाद दूसरे चरण में प्रदेश के शेष जिले में सर्वेक्षण होगा।

उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण से इन समुदायों की जानकारी एकत्र की जायेगी और जानकारी के आधार पर इन समुदायों के विकास के लिये कार्यक्रम बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण दल यह सुनिश्चित करें कि सर्वेक्षण से एक भी परिवार नहीं छूटे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सर्वेक्षण के लिये दिये गये प्रस्ताव पर तुरंत सहमति दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। कार्यशाला में क्षेत्रीय प्रमुख घुमन्तु कार्य श्री गौरेलाल ने सर्वेक्षण कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि वह विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु समुदायों के बीच में पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे है। उन्होंने कार्य के दौरान हुए अनुभवों पर आधारित इन समुदायों की समास्याओं से जुड़े अनेक संस्मरण सुनाये और कहा कि इन समुदायों के विकास के लिये व्यवस्थित कार्य योजना जरूरी है और सर्वेक्षण का डाटा महत्वपूर्ण होगा। कार्यशाला को मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर, अध्यक्ष विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु समुदाय विकास अभिकरण श्री बाबूलाल बंजारा ने भी संबोधित किया।

प्रारंभ में प्रमुख सचिव विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु समुदाय विकास विभाग श्री ई. रमेश कुमार और कार्य पालक निदेशक जन अभियान परिषद डॉ. बकुल लाड ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर जानकारी दी। कार्यशाला में जनअभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक डॉ. बकुल लाड और संचालक विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु समुदाय विकास विभाग श्री नीरज वशिष्ठ ने एमओयू का दस्तावेज एक दूसरे को सौंपा। इस अवसर पर विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु समुदाय विभाग द्वारा तैयार किये गये पोस्टर का विमोचन भी किया गया।

स्वतंत्रता आंदोलन में गौरवमयी संघर्ष की याद दिलाती है कोल जनजाति : मंत्री डॉ. शाह

भोपाल (नप्र)। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने बताया है कि मध्यप्रदेश सरकार जनजातीय वर्ग के लोगों के उत्थान के लिये वचनबद्ध है। प्रदेश की प्रमुख पिछड़ी जनजाति में कोल जनजाति तीसरी प्रमुख पिछड़ी जनजाति है। उन्होंने कहा कि कोल जनजाति स्वतत्रंता आंदोलन में गौरवमयी संघर्ष की याद दिलाती है। संघर्षमयी इतिहास, उनकी शैली और संस्कृति स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिये जानी जाती है। मध्यप्रदेश में 10 लाख से भी ज्यादा कोल जनजाति के लोग निवासरत है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, नरसिंहपुर, जबलपुर और डिण्डौरी में मुख्यतः निवासरत है। बढ़ी आबादी कोल जनजाति केवल मध्यप्रदेश ही नहीं देश के उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्य में भी निवास करती है। यह खरवार समूह की एक प्राचीन जनजाति है। ये स्वयं को शबरी माता का वंशज मानते है। कोल शब्द कुल से निकला है, जो समस्त का रूप है।

ग्रामीण संस्कृति की धड़कन है वाद्ययंत्र

मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि कोल जनजाति का मुख्य जीविकोपार्जन वनोपज संग्रहण, कृषि और मजदूरी पर आधारित है। प्रकृति की पूजा करने वाली यह जनजाति जंगल, नदियों और पहाड़ों से गहरा नाता रखती है। कोल समाज के पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और वाद्ययंत्र आज भी ग्रामीण संस्कृति की धड़कन है। सरकार और समाज मिलकर कोल जनजाति के उत्थान और सम्मान के लिये कार्य कर रहे है। सरकार द्वारा जनजातियों के विकास के लिये संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने से और औद्योगिकरण के विकास से कोल जनजाति भी विकास की और अग्रसर है।

शिक्षा और रोजगार पर शासन का फोकस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जनजाति वर्ग के चहुँमुखी उत्थान के लिये राज्य और केन्द्र सरकार के द्वारा छात्र-छात्राओं के विकास के लिये किये जा रहे समन्वित प्रयासों का परिणाम है कि कोल जनजाति के छात्र-छात्राएँ आज उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे है। राज्य शासन द्वारा म.प्र. प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में सफल होने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अभ्यर्थियों को देय राशि प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 40 हजार मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 60 हजार एवं साक्षात्कार उपरांत सफल होने पर 50 हजार की राशि प्रदान की जाती है।

जल गंगा संवर्धन अभियान

सिपरी साफ्टवेयर की बारीकियां सीखने आज भोपाल आएगा महाराष्ट्र का 9 सदस्यीय दल

भोपाल (नप्र)। जल गंगा संवर्धन अभियान में मनरेगा परिषद द्वारा किए गए नवाचार का अध्ययन करने महाराष्ट्र सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का 9 सदस्यीय दल दो दिवसीय दौरे पर मध्यप्रदेश आएगा। यह दल 12 जून को भोपाल आएगा। साथ ही फील्ड में जाकर सिपरी साफ्टवेयर खेत तालाब और अमृत सरोवरों के निर्माण स्थल चयन में किस तरह से काम करता है, दल के सदस्य इसकी बारीकियां सीखेंगे।

इसके साथ ही मनरेगा परिषद द्वारा कार्ययोजना को लेकर तैयार किए गए प्लानर ऐप के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस दौरान दल के सदस्य 12 जून को भोपाल एवं 13 जून को रायसेन जिले के सांची विकासखंड का भ्रमण करेंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत बारिश के पानी को बचाने के लिए बनाए जा रहे खेत तालाब, अमृत सरोवर और कूप रिचार्ज पिट का कार्य देखेंगे। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग द्वारा बीते दिनों राष्ट्रीय समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। समीक्षा कार्यक्रम में मनरेगा आयुक्त-संचालक वाटरशेड मिशन श्री अवि प्रसाद ने मध्य प्रदेश में जल संरक्षण व संवर्धन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यों के चयन तथा मॉनिटरिंग के लिए किए गए नवाचार सिपरी SIPRI सॉफ्टवेयर (A Decision Support System) का प्रस्तुतीकरण किया था, जिसकी भारत सरकार द्वारा प्रशंसा की गई थी। साथ ही भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के इस नवाचार को समीक्षा कार्यवाही विवरण में रेखांकित किया। राष्ट्रीय समीक्षा में आए हुए अन्य राज्यों के प्रमुख सचिवों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने भी सिपरी (SIPRI) की उपयोगिता की सराहना की और अपने राज्यों में भी इसके उपयोग की रुचि दिखाई थी।

भोपाल स्मार्ट सिटी के काम देखने निकले कलेक्टर

तुलसीनगर में बिल्डिंग को 5 मंजिला करने को कहा, गांवों के अस्पताल भी देखे

भोपाल (नप्र)। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह बुधवार को अचानक स्मार्ट सिटी के काम देखने निकल पड़े। उन्होंने तुलसी नगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग देखी और पार्किंग समेत कई मुद्दों पर निर्देश दिए। साथ ही बिल्डिंग की ऊंचाई 4 से 5 मंजिल करने को कहा। कलेक्टर सिंह ने तुलसी नगर स्थित स्मार्ट सिटी के निर्माण अधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया। बिल्डिंग में पार्किंग स्पेस कम होने के कारण आसपास की जगह में पार्किंग बनाए जाने की निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी की सीईओ अंजू अरुण कुमार एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने हुजूर तहसील की नव निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण भी किया। हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया भी मौजूद थे।

संजीवनी क्लीनिक भी पहुंचे कलेक्टर: कलेक्टर ने सिमरिया गोद, सूरज नगर की सरदार वल्लभ भाई पटेल सिविल डिस्पेंसरी एवं संजीवनी क्लीनिक का निरीक्षण भी किया। इस दौरान संजीवनी क्लीनिक में पदस्थ डॉ. अनसूया बामनिया ने बताया कि इस क्षेत्र में प्रतिदिन 50 के लगभग ओपीडी रहती है। पॉलीक्लिनिक में 12 से अधिक जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

पॉली हाउस का निरीक्षण किया

कलेक्टर सिंह ने कृषक सौदान सिंह कुशवाह द्वारा संचालित पॉली हाउस का भी निरीक्षण किया। कुशवाह ने बताया कि उन्होंने दो एकड़ भूमि में जरवेरा एवं जिप्सोफिला फूलों की खेती के लिए 40 लाख रुपए का लोन लेकर पॉली हाउस की स्थापना की है। जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुआ। इस खेती से उन्हें प्रतिवर्ष 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। भ्रमण के दौरान लालघाटी चौराहे पर भीख मांग रही महिलाओं को देखकर कलेक्टर सिंह ने तत्काल संबंधित भिक्षु दलों को रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजने के निर्देश दिए।उन्होंने चेतावनी दी कि जो व्यक्ति रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं जाना चाहते, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संपादकीय

स्वर्णिम कालखंड : तस्वीर का एक पहलू

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा देश की राजधानी सहित सभी प्रादेशिक राजधानियों में मुख्यमंत्रियों के माध्यम से अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर रही है। इसके तरह मोदी सरकार के इन निरंतर 11 साल की कार्यकाल में भारत की आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर प्रगति का ब्यौरा दिया जा रहा है। लेकिन सरकार के कामकाज की यह गुलाबी तस्वीर तस्वीर का एक पहलू है और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जहां काफी काम करने की जरूरत है। गौरतलब है कि नरेन्द्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई 2014 को शपथ ली थी। यह पहली बार था कि जब कांग्रेस से इतर वैचारिक पृष्ठभूमि और राष्ट्रवाद को अपना केन्द्रीय विचार मानने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर केन्द्र में सत्तासीन हुई थी। पहले कार्यकाल में मोदीजी ने पड़ोसियों से बेहतर सम्बन्ध बनाने के साथ साथ आर्थिक प्रगति की रफ्ता र तेज करने, भाजपा का राजनीतिक अश्वमेध शुरू करने के साथ साथ नोटबंदी जैसे फैसले भी किए, जिसकी उपयोगिता और जरूरत पर आज भी बहस होती है। हालांकि पहले कार्यकाल के अंतर में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के फैसले ने मोदी को एक दमदार पीएम के रूप में स्थापित किया और भाजपा दूसरे कार्यकाल में पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। दूसरे, कार्यकाल में मोदी सरकार ने राम मंदिर, तीन तलाक विरोधी कानून, कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे फैसले किए और उन अमल भी किया। कश्मीर में काफी हद तक शांति आई। कोरोना काल में इस महामारी का बेहतर प्रबंधन और 80 गरीबों को मुफ्ती राशन जैसी योजनाएं सरकार के खाते में लिखी गईं। लेकिन दूसरी तरफ देश में साम्प्रदायिक और धार्मिक विभाजन भी गहराता गया है। हालांकि हाल में पहलगाम आंतकी हमले के बाद देश में एकजुटता का नया और सराहनीय माहौल दिखाई दिया, जिसे कायम रखने की जरूरत है। इसी तरह देश में भ्रष्टाचार कम होने के दावे में भी ज्यादा दम इसलिए नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान कई बार राजनीति से प्रेरित लगता है। दूसरे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाइयां भी उनका मनोबल तोड़ने में नाकाम रही हैं। उलटे भ्रष्टाचार ने वहां भी जड़ें जमा ली हैं, जहां वह पहले कम था। सरकार का दावा है कि 11 साल की यह यह यात्रा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर आधारित रही है। इन वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रगति की है। आर्थिक मोर्चे पर भारत 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने निवेश और नवाचार को बढ़ावा दिया। महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर रहा, जिसमें 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं को दिए गए और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी 28 फीसदी बढ़ी। एक अहम उपलब्धि बीते 11 वर्षों में भारत में गरीबी का घटना है। इस अवधि में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। सरकार ने चार करोड़ मकान बनाए हैं और आगे तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य है। इसमें संदेह नहीं कि मोदी सरकार ने दुनिया में एक फैसले लेने वाली और उस पर अमल करने वाली सरकार की छवि बनाई है। वैसे केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के अनुसार मोदी सरकार के 11 साल संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड है। इसमें सच्चाई तो है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, यह भी ध्यान में रखना होगा। खासकर विदेश नीति के मामले में। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह भारत अलग थलग पड़ा, वह गंभीर चिंता का विषय है।

देश में सबकुछ भारतीय होना चाहिए

नजरिया

रघु ठाकुर
लेखक समाजवादी विचारक हैं।

धीरेन्द्र शास्त्री कुछ संघ समर्थक व धार्मिक व्यक्ति के रूप मे चर्चित हैं, और कुछ अनर्गल टिप्पणियों के कारण अपने आश्रम में सेन समाज के व्यक्ति को जाति छिपाने के अपराध में वे उठक-बैठक लगवा चुके हैं। जिसे सारे देश ने देखा है। अभी हाल में उन्होंने एक नया जुमला फेंका है कि वे हिन्दू ग्राम्य बसायेंगे जो भविष्य में हिन्दू राष्ट्र के आधार और माध्यम बनेंगे। उनके हिन्दू ग्राम की क्या कल्पना है यह अभी रहस्य के गर्भ में है, परंतु एक चर्चा तो उन्होंने देश में शुरू करा ही दी है। इस चर्चा को संघ धीरे-धीरे फैलायेगा। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री फड़नवीस ने हिन्दू अर्थव्यवस्था की चर्चा एक सम्मेलन में की थी।

देश में काफी चर्चित नाम हैं। उनके धार्मिक अनुयायी उन्हें बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। सत्ता के साथ उनके रिश्ते भी अब उन्हें चर्चा के केन्द्र में लाये हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम गये थे। वहां श्री धीरेन्द्र शास्त्री कैंसर अस्पताल का निर्माण करा रहे हैं। यह अस्पताल कैसा होगा, क्या स्वरूप होगा, क्या सरकार की हिस्सेदारी होगी या निजी खिलाड़ियों की पूंजी लगेगी, यह सब सवाल अभी अनुत्तरित हैं। मीडिया के अनुसार प्रधानमंत्री जी ने वहां पर्ची लगाई थी। बाद में बताया कि श्री शास्त्री की मां की इच्छा उनकी शादी की है। प्रधानमंत्री उन्हें शादी में आने का वादा भी कर आये हैं। प्रधानमंत्री की बागेश्वर यात्रा के उद्देश्य क्या हैं यह तो वे ही बेहतर जानते होंगे? परंतु, एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि उन्हें बागेश्वर धाम के प्रचार और लोकप्रियता से कुछ भविष्य में संकट के संकेत नजर आ रहे हैं। इसीलिए उसकी तैयारी संघ और प्रधानमंत्री ने अभी से करने की सोची है। क्योंकि श्री धीरेन्द्र शास्त्री,1 करोड़ हिन्दुओं को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संगठित करने की घोषणा कर चुके हैं।

संघ चर्चित लोगों का उपयोग करने में और उपयोग के बाद उन्हें यथास्थान पहुंचाने में बहुत ही निष्णात है।

एक जमाने में बाबा रामदेव को देश में एकमात्र योगगुरु के रूप में प्रतिष्ठित कराया। चुनाव में उनका भरपूर उपयोग किया। अब वे हरिद्वार में पतंजलि के नाम से व्यापार कर रहे हैं। अन्ना हजारे के माध्यम से टू-जी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया। अब अन्ना हजारे लगभग गुमनामी की खोह में हैं। वीपी सिंह के माध्यम से बोफोर्स कांड की चर्चा हुई। अब वीपी सिंह दुनिया में नहीं हैं, और चर्चा में भी नहीं है,परंतु जिस शक्ति का जनसमर्थन संघ को लेना था वह मिल चुका है।

धीरेन्द्र शास्त्री कुछ संघ समर्थक व धार्मिक व्यक्ति के रूप मे चर्चित हैं, और कुछ अनर्गल टिप्पणियों के कारण अपने आश्रम में सेन समाज के व्यक्ति को जाति छिपाने के अपराध में वे उठक-बैठक लगवा चुके हैं। जिसे सारे देश ने देखा है। अभी हाल में उन्होंने एक नया जुमला फेंका है कि वे शिन्दू ग्राम्य बसायेंगे जो भविष्य में हिन्दू राष्ट्र के आधार और माध्यम बनेंगे। उनके हिन्दू ग्राम की क्या कल्पना है यह अभी रहस्य के गर्भ में है, परंतु एक चर्चा तो उन्होंने देश में शुरू करा ही दी है। इस चर्चा को संघ धीरे-धीरे फैलायेगा। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री फड़नवीस ने हिन्दू अर्थव्यवस्था की चर्चा एक सम्मेलन में की थी।

हिन्दू अर्थव्यवस्था भी संघ का एक एजेंडा है। हिन्दू अर्थव्यवस्था के नाम पर अन्य धर्मावलंबी चिह्नित किए जायेंगे। क्या उनसे व्यापार बंद किया जायेगा? इस हिन्दू अर्थव्यवस्था में सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, मुसलमान आदि शामिल होंगे या नहीं यह भी अभी भविष्य के गर्भ में है या हो सकता है कि पहले चरण में मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जाए फिर अन्यों का नंबर आए। निसंदेह आज की तारीख में हिन्दू ग्राम या हिन्दू अर्थव्यवस्था के जुमले मजाक जैसे लग सकते हैं, अगंभीर भी कहलायेंगे, परंतु यह वह बीज है जो भविष्य में विभाजन का आधार बन सकते हैं। इस बहस से लोगों के मन में एक मानसिक विभाजन का कीटाणु तो प्रवेश कर ही रहा है। ये विषय धीरे धीरे देश-गांव-धर्मगुरुओं की सभाओं में उठाये जायेंगे। धीरे धीरे देश में इसके लिए वातावरण तैयार किया जायेगा।

यदि हम इतिहास को बारीकी से देखें तो उन्नीसवीं सदी में जब हिन्दू और मुसलमानों के अलग अलग राष्ट्र की चर्चा शुरू हुई थी तब वह हंसी मजाक का विषय था। लोग उसे गंभीरता से नहीं नहीं लेते थे। परंतु देश की कट्टरपंथी ताकतों व मानस ने कुछ ही वर्षों में, इसे ज्वलंत मुद्दा बना दिया था। हिन्दू व मुस्लिम कट्टरपंथ दोनों अपने अपने ध्वजवाहक बन गये और अंततः देश का बंटवारा हो गया। कई घटनाएं आरंभ में छोटी लगती हैं, परंतु क्रमशः मानसिक खुराक खाते खाते वे विषबेल की तरह फैल जाती है। भारत सरकार या प्रधानमंत्री जी ने, संघ या भाजपा ने अभी तक उनके इन बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। प्रशासनिक आधार पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया। खालिस्तान की मांग करने वाले राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। कोई और मजहब वाले कहें तो राष्ट्रद्रोही हो जायेंगे, पर बागेश्वर धाम को सत्ता और संघ का संरक्षण है। यह आश्चर्यजनक है कि भाजपा, संघ और सरकार ही नहीं बल्कि भारत की सम्पूर्ण संसदीय राजनीति इन गंभीर आपराधिक बयानों पर मौन है। जिस छतरपुर के गांव में यह बागेश्वर धाम है, वहां बुन्देलखण्ड में आये दिन जातीय दमन व हिंसा की घटनाएं रोज अखबारों में छपती हैं। कुछ दिन पहले अनुसूचित जाति के पुलिस वाले को बारात में घोड़े पर बैठने से रोका गया बड़ी मुश्किल से पुलिस के संरक्षण में उसकी बारात निकल पायी। कुछ ही दिन पहले ऐसी ही जातीय भेदभाव की घटना अखबारों में छपी जिसमें किसी छोटी जातिवाले दूल्हे को घोड़े पर बैठने से रोका गया। खुद धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने बागेश्वर धाम के आसपास के लोगों को उनके घरों से बलात हटा दिया। उनके साथ मारपीट की। हवाई फायर करके भयभीत किया। परंतु, केवल कानूनी औपचारिकता के अलावा कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि उन्हें कुछ ही घंटों में हंसते-मुस्कराते जमानत मिल गई। यह स्थिति अकेले बुंदेलखंड और मध्यप्रदेश की नहीं है, बल्कि समूचे उत्तर भारत में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के बहरामपुर गांव में हाइकोर्ट के हस्तक्षेप से तीन सौ साल बाद शिव मंदिर में दलितों को पूजा का अधिकार मिला। ऐसी कितनी घटनाएं हम लोग रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं। आज जब देश में एक धर्म का शासन नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था है, तब यह स्थिति है तो एक धर्म का राष्ट्र बनने के बाद या एक धर्म का गांव बसने के बाद क्या स्थिति जन्म लेगी यह एक भयावह कल्पना है। कहीं यह हिन्दू गांव फिर से देश के मानसिक और वास्तविक विभाजन का कारण तो नहीं बनेगा?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो संविधान रक्षक हैं उसे इन विषयों पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। असंवैधानिक लक्ष्यों के संगठनों या उद्घोषकों के विरुद्ध न केवल आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि उन्हें जनतांत्रिक अधिकारों से वंचित करना चाहिए।

श्री धीरेन्द्र शास्त्री ने जो चर्चा शुरू की है उस पर देश के अन्य इलाकों में भी अलग-अलग प्रयोग चल रहे हैं। बागेश्वर धाम के नजदीक हिन्दू ग्राम बसाने के ऐलान का कई साधू संतों ने सार्वजनिक स्वागत भी किया है। इसका भूमिपूजन भी धीरेन्द्र शास्त्री ने किया है। उनका कहना है कि यही हिन्दू ग्राम भविष्य के हिन्दू राष्ट्र की आधारशिला बनेंगे। समाचार-पत्रों से पता चला है कि इस गांव की जमीन केवल सनातनी हिन्दुओं को उपलब्ध कराई जायेगी। फ्लैट सिस्टम से मकान बनेंगे।

धीरेन्द्र शास्त्री का यह भी कहना है कि पहले हिन्दू ग्राम बसाये जायेंगे, फिर हिन्दू जिले, फिर प्रांत, फिर हिन्दू राष्ट्र। इस प्रकार के प्रयोग अघोषित तौर पर देश के कुछ और इलाकों में हुआ है। गुजरात के ऊना में कई गांवों में बोर्ड लगाये गये हैं कि हिन्दू राष्ट्र के गांव में आपका हार्दिक स्वागत है। हालांकि अनेक गांव जहां ये बोर्ड लगाये गये हैं उनमें कुछ मुस्लिम व आदिवासी आबादी भी है। अभी तो वहां के लोग भयवश चुप हैं। क्यों कि केन्द्र और गुजरात, केन्द्र और मध्यप्रदेश में कहने को दो इंजन की सरकार है, वास्तव में एक ही इंजन यानी संघ की सरकार है। मैं चाहता हूं कि देश में ऐसे अनावश्यक प्रश्नों पर निरर्थक बहस न हो, क्यों कि उससे ऐसे विचारों का प्रचार होता है। वे भविष्य में जहरीले बन जाते हैं। यह भी अच्छा है कि किसी गैर हिन्दू धर्मावलंबी ने अभी तक इस पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी या निंदा नहीं की है। यह देश के सहनशील समावेशी मानस का प्रमाण है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय से जरूर मैं अपील करूंगा कि वह इसका संज्ञान ले और इस जहरीले विभाजन के बीज को आरंभ में ही समाप्त करे।

एक और भी खतरा है कि कहीं धर्म के नाम के गांव के बाद जाति आधारित गांव का सिलसिला शुरू न हो जाये। हालांकि देश में पहले भी ग्रामों व शहरों में धर्म व जाति के नाम के मोहल्ले बसे हैं। परंतु यह घटनाएं सदियों पुरानी हैं जब देश गुलाम था और संविधान नहीं बना था। अब हम एक आजाद मुल्क हैं। अब सब कुछ भारतीय ही होना चाहिए।

मोदी का निर्देश और रियल एस्टेट में पारदर्शिता की आवश्यकता

सुधार

अरुण कुमार डनायक
लेखक गांधी विचारों के अध्येता हैं।

प्रधानमंत्री मोदीजी ने हाल ही में हुई 'प्रगति' (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाईमली इम्प्लीमेनटेशन) बैठक में भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा) के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि अधिनियम का सख्त अनुपालन परियोजनाओं की गुणवत्ता, समय पर डिलीवरी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे रेरा के तहत सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं का अनिवार्य पंजीकरण करें और उपभोक्ता शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।

भारत में घर केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व का प्रतीक होता है—हर मध्यमवर्गीय परिवार का सबसे बड़ा सपना। लेकिन आज यह सपना रियल एस्टेट की उलझनों में फंसा हुआ है। अधूरी परियोजनाएं, कब्जे में देरी और लगातार बढ़ती शिकायतें लाखों गृह-क्रेताओं की नियति बन चुकी हैं। समय पर निर्माण न होने से न सिर्फ लागत बढ़ती है, बल्कि उपभोक्ता दोहरी मार झेलते हैं—किराए और होम लोन की। 'प्रगति' जैसे उच्च-स्तरीय ई-गवर्नेंस मंच पर इस मुद्दे का उभरना रियल एस्टेट क्षेत्र में व्याप्त गंभीर समस्याओं को रेखांकित करता है।

2016 में लागू रेरा का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, बिल्डरों की जवाबदेही और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है। परंतु व्यवहार में रेरा अनेक चुनौतियों से घिरा है—सीमित अधिकार, जटिल अपील प्रक्रियाएं, सेवानिवृत नौकरशाहों की नियुक्ति, पेशेवर हितसाधकों एवं व्यवसाय विशेषज्ञों की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप इसके प्रभाव को कमजोर करते हैं।

बिल्डरों को असंवेदनशील नौकरशाही की प्रशासनिक बाधाओं, जटिल अनुमोदन प्रणाली, पक्षपातपूर्ण निर्णय और वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परियोजनाएं लटक रही हैं। परिणामस्वरूप, रेरा के तहत पंजीकृत परियोजनाएं कम हैं, लेकिन शिकायतें अधिक, जो इसके कमजोर क्रियान्वयन को उजागर करता है।

सराहनीय उद्देश्य के बावजूद रेरा की क्रियान्वयन क्षमता सीमित है। रेरा अधिकारियों के पास सीमित दंडात्मक शक्ति तो है, लेकिन उनकी सिफारिशों को लागू कराने का कोई ठोस तंत्र नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा रेरा को गंभीरता से लागू न करने के कारण यह कानून निष्प्रभावी हो गया है। आदेशों की अवहेलना होने पर उपभोक्ता को वर्षों की कानूनी प्रक्रिया के लिए न्यायालय जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता, और कई बार रेरा के वरिष्ठ अधिकारी ही आवंटियों को हाईकोर्ट जाने की सलाह देते हैं।

रेरा, बिल्डर का पंजीकरण रद्द होने की स्थिति में, आवंटितियों को संगठित कर उनकी संस्था द्वारा शेष निर्माण कार्य पूरा करने की अनुमति दे सकता है। व्यावहारिक रूप से, बिल्डर के सहयोग के बिना अनुभवहीन आवंटियों के लिए पंजीकृत संस्था बनाना और मार्टगेज भूसंपत्ति का पंजीकरण कराना कठिन होता है। यह प्रक्रिया प्रायः लालफीताशाही की जटिलताओं में उलझकर रह जाती है।

रेरा अक्सर अधूरे निर्माण कार्यों को बिना लाभ के पूर्ण करने का दायित्व राज्यों के अर्ध-शासकीय निकायों, जैसे गृह निर्माण मंडल, को सौंपता है। ये निकाय प्रायः रेरा के आदेशों का पालन नहीं करते, और शासन स्तर पर भी कोई प्रभावी हस्तक्षेप नहीं होता।

रेरा अक्सर आवंटियों के पक्ष में निर्णय देता है, लेकिन बिल्डर से राशि वसूलने में गृह खरीदारों को प्रशासनिक सहायता नहीं मिलती। क्रेता जिलाधिकारी कार्यालय में रिकवरी रेवेन्यू सर्टिफिकेट दाखिल कर वसूली शुरू कर सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद धीमी और अप्रभावी है। जब सरकार स्वयं कर वसूली में असमर्थ है, तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ईश्वर के भरोसे ही रह जाती है। रेरा में पदस्थ पूर्व नौकरशाह भी क्रेताओं के हित में जिला प्रशासन पर अपने प्रशासनिक रसूख का उपयोग कर वसूली हेतु दबाव नहीं बनाते।

रेरा के प्रावधानों में एक महत्वपूर्ण विसंगति यह है कि अपीलीय अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री की तरह निष्पादनीय होता है, लेकिन रेरा में नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह परिवाद की सुनवाई के बाद सिविल न्यायालय के समकक्ष निर्णय दे सके। यह विसंगति रेरा की प्रथम स्तर की कार्यवाही की प्रभावशीलता को सीमित करती है और आवंटितियों को त्वरित न्याय प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है।

रेरा को बिल्डर, आबंटी या रियल एस्टेट एजेंट से आवश्यक जानकारी मांगने और जांच करने का अधिकार है। जांच के बाद, यह दीवानी आदेश जारी कर सकता है, लेकिन आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। धोखाधड़ी के मामलों में पुलिस केस दर्ज करने के लिए आबंटियों को स्वतंत्र रूप से भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई करनी पड़ती है।

प्रधानमंत्री का रियल एस्टेट क्षेत्र में हस्तक्षेप सुधारों की दिशा में प्रेरणादायक और सकारात्मक कदम है। यह हस्तक्षेप रेरा के प्रभावी क्रियान्वयन, बिल्डरों की जवाबदेही सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित समाधान और गृह खरीदारों के लिए समयबद्ध मुआवजा प्रदान करने की दिशा में आशा जगाता है। फिर भी, प्रशासनिक देरी, जटिल मंजूरी प्रक्रियाओं, औरआपराधिक कार्रवाई की सीमाओं जैसे मुद्दों को दूर करने के लिए और अधिक समन्वित प्रयासों की जरूरत है। यह कदम एक महत्वपूर्ण शुरुआत है, लेकिन अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। रेरा को सख्ती से लागू करने का केंद्र का निर्देश उपभोक्ता-हितैषी मंशा को दर्शाता है, लेकिन अब राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे स्थानीय विकास प्राधिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित करें और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करें।

यदि 'घर' को 'भरोसे' से जोड़ना है, तो कानून, प्रशासन और निजी क्षेत्र को मिलकर उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करनी होगी – यही विश्वास इस क्षेत्र की असली बुनियाद बनेगा। उपभोक्ताओं का विश्वास और बिल्डरों की ईमानदारी साथ मिलकर ही एक जवाबदेह और न्यायपूर्ण आवास व्यवस्था की नींव रखी जा सकती है। रेरा को बिल्डरों के खिलाफ कठोर कदम, जैसे दंडात्मक कार्रवाई, जुर्माना, बैंक खातों पर रोक, या पंजीयन रद्द करना, अंतिम उपाय के रूप में अपनाना चाहिए। इसके बजाय, पहले चरण में सुधारात्मक और नियामक उपायों पर ध्यान देना अधिक प्रभावी होगा। रेरा को बिल्डरों और क्रेताओं के बीच गांधीजी के अहिंसक, मध्यस्थता, और आपसी सुलह आधारित दृष्टिकोण अपनाकर रियल एस्टेट क्षेत्र में निष्पक्षता, पारदर्शिता, और विकास को बढ़ावा देना चाहिए। यह क्रेताओं के हितों की रक्षा के साथ-साथ क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करेगा। सौहार्द्रपूर्ण समाधान और विश्वास बढ़ाने के लिए रेरा को चाहिए कि वह भू संपदा विशेषज्ञों के साथ समयबद्ध मध्यस्थता सत्र आयोजित करे, बिल्डरों को सुधार का अवसर दे, आपसी सहमति पर आधारित पंचायत-शैली के फैसलों से विवाद सुलझाए, और क्रेताओं व बिल्डरों के लिए रेरा नियमों हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाए।

प्रेम को पाने का रास्ता क्या?

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया
लेखक स्तंभकार हैं।

स्त्री को हमेशा ही सौम्य और भावुक कृति माना गया है। परन्तु आजकल जिस प्रकार के समाचार हमें सुनने या देखने को मिल रहे है। उन्हें देखकर विश्वास ही नहीं होता कि क्या सचमें हम खुद को मनुष्य कहलाने के काबिल रहे है? शिलांग के पहाड़ों को हम किस प्रकार याद रखेंगे? जहां प्रकृति की सुन्दरता का दर्शन होता हो वही किसी के जीवन का अंत करने की कहानी रची गई। वो भी तब जब हाथों की मेहंदी का रंग हाथों की लकीरों को नए रिश्ते की डोर से बाँध रहा हो।

आखिर किस दिशा की तरफ हम जा रहे है? क्या हमारे परिवारों की नींव इतनी कमजोर हो चुकी है, कि जिस पर हम मजबूत रिश्तों की इमारत नहीं रख पा रहे? क्या बेटी बचाओ के नारे ने बेटियों के भीतर से संवेदनाओं को खत्म कर दिया है? हम यह क्यों नहीं समझ पा रहे कि समाज के नव- निर्माण की बात करते-करते हम इसका संतुलन बिगाड़ रहे है।प्रेम और वासना में अंतर करना भूल चुके है। आखिर यह कैसा प्रेम है जो किसी अन्य से जीने का अधिकार ही छीन लें। आज के जीवन में जहां हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, महंगे कपड़े और दुनिया की सैर कराने में सबसे आगे रहते है,काश उतना ही ध्यान हमने अपनी आगामी पीढी को समझने और उनको रिश्तों की वास्तविकता को समझाने में लगाया होता, तब हमें किसी मुस्कान या सोनम के किस्सों की दास्ताँ नहीं सुननी पड़ती। इन भयावह किस्सों को जब हम दोहराते है, तब हमारे भीतर सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों मानवीय संवेदनाए इतनी क्रूर हो गई है? क्या सच में हमनें दिल की अपेक्षा दिमाग से काम लेना आरम्भ कर दिया है? जिसके परिणामस्वरूप हम मात्र अपने हित की चिंता करते है।

कुछ दिन पहले जब शिलांग में गायब हुए जोड़े के बारे में समाचार आया था, तब लगा शायद कुछ अनहोनी हो गई हो। सबने अपने-अपने स्तर पर इस जोड़े के लिए प्रार्थनाएं भी की थी। लेकिन वास्तविकता के पर्दे के पीछे छिपा सच जब उजागर हुआ, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा।हम यह क्यों भूल रहे है कि वास्तविकता हमेशा से ही आश्चर्यजनक परिस्थितियाँ खड़ा करती है। सोनम का केस हो या मुस्कान का धोखा यह हमारे आज के समाज का वीभत्स रूप दिखा रही है। यह उन स्त्रीयों पर भी प्रश्नचिंह लगा रही है , जो सच में अपने प्रेम को पवित्र रूप मानकर अपना जीवन जी रही है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है , परन्तु यहाँ तो लगता है कि जिस तालाब के किनारे बैठो वहां की मछली गन्दी है। हम आज भी स्त्रियों की सुरक्षा की बात पर चिंतित है , क्योंकि ऐसा नहीं है की सभी स्त्रीयां एक अच्छा जीवन जी रही है, पर जब सोनम जैसे केस का सामना समाज को करना पड़ता है, तब इसका खामियाजा उन महिलाओं को चुकाना पड़ता है, जिन्हें सच में समाज की मदद की आवश्कता है।

हम एक भ्रमित राह की डगर पकड़ चुके है। हमें अपनी बेटियों को स्वत्रंत्रता के साथ-साथ सहजता भी सिखानी होगी। क्योंकि कहीं न कहीं परिवार का दबाव, लडकियों के भीतर कुंठित मानसिकता को जन्म दे रहा है। हमें यह देखना होगा कि अगर हमारी बेटियाँ हमारी इज्जत के लिए किसी ओर से शादी कर लेती है , तो वह बाद में खूंखार कैसे बन जाती है? क्या मात्र शादी कर लेने तक का उनका और हमारा सम्बन्ध होता है? क्या उनके किए घृणित कार्य से परिवार को दुःख नहीं पहुंचता? यह वह क्यों नहीं सोचती? क्षणिक खुशी के लिए अपना और अपने परिवार के साथ किसी अन्य के परिवार को जीवन भर का दुख दे देना क्या उनके लिए अपने प्रेम को पाने का रास्ता है?

वासना और प्रेम में अंतर करना शायद आज की पीढी भूल चुकी है। परिवार से ज़्यादा हमारी खुशी और कोई नहीं चाहता। इस बात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यह हमारे परिवार का प्यार ही है जो हमें पढ़े-लिखे और सुशील जीवनसाथी के चुनाव करने में हमारी सहायता करते है। जिससे की हमारा आगामी जीवन सुखद रहे। हमें बस अपने भीतर के क्षणिक आकर्षण को प्रेम न मानकर धरातल की सच्चाई को समझना होगा। यह नहीं कह रही हूँ की प्रेम-विवाह न करें या वह सफल नहीं होते। पर यदि आप शादी जसे पवित्र बंधन में बंध गए है तब अपने जीवनसाथी के बारे में कुछ गलत करने का विचार भी मन में न लाए। ऐसा आप मात्र किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं अपितु दो परिवारों के साथ अन्याय कर रहे है? तो अपने भीतर के क्षणिक सुख को प्रेम न मानें, जो बदला ले वह प्रेम नहीं बल्कि आपका स्वार्थ है और परिणाम हमारे सामने है, किसी को मारकर अपना जीवन जिया ही नहीं जा सकता। धैर्य से काम लें और यथार्थ को समझें।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

महंगाई और भ्रष्टाचार : एक अध्ययन

व्यंग्य

राजेंद्र बज
लेखक व्यंग्यकार हैं।

विकास हो रहा है और हर किसी को दिखाई दे रहा है। शहर-शहर, नगर-नगर और डगर-डगर पर विकास का सिलसिला 'बदस्तूर' जारी है। हमारे मालवा में कहा जाता है कि खाना बनाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। कुछ इसी तर्ज पर जिनके माथे विकास का सेहरा बंधता है, उनको सूखे का सामना नहीं करना पड़ता। यही नहीं उन्हे यह चिंता भी नहीं सताती कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी बैठे-बैठे कैसे खा पाएगी ? उधर महंगाई बढ़ रही है और भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। लेकिन हम नए खयालात वाले है, पुराने मुद्दों को हमने बिसरा दिया है। आजकल तो कोई महंगाई और भ्रष्टाचार की बात करता है तो उसे दकियानूसी विचारधारा वाला मान लिया जाता है।

जो आधुनिक विचारधारा वाले हुआ करते है, समय के साथ समझौता कर लिया करते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे प्रैक्टिकल होना कहा जाता है। चतुर सुजान कहते है कि जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी प्रकार महंगाई और भ्रष्टाचार की काट महंगाई और भ्रष्टाचार से की जा सकती है। भ्रष्टाचार का सर्वव्यापीकरण महंगाई के दमन में सहायक होता है। वैसे इस मामले में बहुत सीधा सा गणित यह भी है कि भ्रष्टाचार का राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक परिवेश में व्यापक विस्तार होने के चलते इन वर्गों पर महंगाई का कोई खास असर देखने में नहीं आता। एक तरफ जब देने को मजबूर होना होता है तो दूसरी तरफ लेने का अधिकार भी स्वतः ही मिल जाया करता है।

एक जमाना था जब आदमी की अनिवार्य आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान को ही शुमार किया जाता था। लेकिन अब रोटी और मकान की तो पक्के तौर पर गारंटी है। रहा सवाल कपड़े का, तो कृपया इंतजार कीजिए, आने वाली चुनावी बेला में राजनीतिक बिरादरी का कोई दिग्गज महामानव यह घोषणा भी कर सकता है कि वह चुनाव जीतने पर कौन से 'ब्रांड' का कितना कपड़ा हर आदमी को देगा ! लेकिन यह भी सच है कि आजकल के जमाने में महज रोटी, कपड़ा और मकान से ही जीवन की गाड़ी नहीं चला करती। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए संवेदनशील सरकार ने तमाम तरह की खैराती योजनाओं का भी भरपूर बंदोबस्त कर रखा है।

वैसे इसमें भी कोई दो मत नहीं कि आजकल जीवन जीना बहुत आसान हो गया है। अब हमारे कितने भी अशुभ कर्म का उदय हो जाए, फसल बिगड़ जाए या घर में आग लग जाए, हम सरकार से गुहार कर सकते हैं। दरअसल बीते जमाने की सरकारों की तुलना में आजकल की सरकार बहुत दयालु एवं दातार हो चली है। दरअसल लोकतंत्र की यही खासियत है कि हर एक नागरिक को 'मुल्क का मालिक' करार दिया जाता है। तथाकथित राजनेता, अपने आपको जनसेवक निरूपित किया करते है। तमाम छोटे बड़े अधिकारी एवं कर्मचारी भी जनसेवक कहलाते हैं। इस समय इन दोनों वर्गों में जनसेवा का भाव उछाल मारता नजर आता है।

दरअसल महंगाई और भ्रष्टाचार से वही वर्ग पीड़ित हुआ करता है , जो नैतिकता का दम भरता हो। कहा जाता है कि ऊपर वाला हर किसी के जीवन काल में समय-समय पर ऐसे अनेक अवसर उपस्थित कर देता है जिसके सहारे वह जिंदगी की गाड़ी को बहुत आसानी के साथ खींच सकें। इस मामले में यह उल्लेख जरूरी है कि हर तिल्ली में तेल होता है, बशर्त तिल्ली में से तेल निकालने का आदमी में माद्दा हो। वास्तव में अवसर को भुनाने की कला यदि आदमी में हो, तो आपदा में भी अवसर खोजे जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आदमी की इच्छाशक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि बंद मुट्ठी में से भी चीज निकाल सकें।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर विशेष

अतुल गोयल

लेखक न्यूयॉर्क की कंपनी में सॉफ्टवेयर डवलपमेंट इंजीनियर हैं

बाल श्रम और मौलिक अधिकारों का हनन

हर वर्ष 12 जून को 'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस' मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2002 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने बच्चों को मजदूरी से मुक्त कराने और उनके बचपन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से की थी। वर्ष 2025 में इस दिवस की थीम है 'प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम किया जाना बाकी है- आइए प्रयासों में तेजी लाएं!' यह थीम आज के समय की जमीनी सच्चाई को बखूबी दर्शाती है क्योंकि वैश्विक स्तर पर लाखों बच्चे अब भी उस अंधेरे दलदल में फंसे हैं, जिसे बाल श्रम कहते हैं, जो उनके मौलिक अधिकारों के साथ ही उनके जीवन की संभावनाओं को भी निगल रहा है। बाल श्रम कोई सरल या सतही समस्या नहीं है। यह उस गंभीर सामाजिक विडंबना का परिणाम है, जिसमें समाज, सरकार, उद्योग और व्यक्तिगत स्वार्थ की जटिलताएं आपस में उलझी हुई हैं। किसी भी बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम पर लगाना, उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल जैसी मूलभूत चीजों से दूर करना, सीधा-सीधा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 यह स्पष्ट करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक कार्यस्थल पर नियोजित नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद छोटे-छोटे ढाबों, चाय की दुकानों, ईंट भट्टों, कालीन बुनाई केंद्रों, बीड़ी, कांच, पटाखा और चूड़ी उद्योगों में काम करते मासूम बच्चों को देखना एक आम दृश्य है।

बाल श्रम की वैश्विक स्थिति को देखें तो आईएलओ और यूनिसेफ की 2023 की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 16 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं, जिनमें से लगभग 8 करोड़ बच्चे खतरनाक श्रम कार्यों में लगे हुए हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि हर 10 में से एक बच्चा अपने बचपन के बजाय किसी मजदूरी की जगह पर खड़ा है। इन 16 करोड़ बच्चों में से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लगभग 4.9 करोड़, अफ्रीका में लगभग 8.6 करोड़, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 1.1 करोड़ बच्चे इस समस्या से पीड़ित हैं। इस समय सर्वाधिक गंभीर स्थिति उप-सहारा अफ्रीका की है, जहां प्रत्येक दसवां बच्चा श्रमिक है। भारत की स्थिति भी चिंताजनक है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2023 तक भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 1.01 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं। हालांकि पिछले दो दशकों में शिक्षा के प्रचार, सरकारी योजनाओं और गैर-सरकारी संगठनों की मेहनत से बाल श्रमिकों की संख्या में गिरावट आई है लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों, घरेलू कामों और खेती-बाड़ी जैसे असंगठित क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति अब भी भारी है। महामारी के बाद की परिस्थितियों में बाल श्रम का पुनरुत्थान देखने को मिला है। कोविड-19 के कारण परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब होने से कई बच्चों को पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना पड़ा।

भारत के कई हिस्सों में बच्चों को आज भी पढ़ाई और खेल के बजाय दिनभर मजदूरी में झोंक दिया जाता है। कभी वे सड़क किनारे भीख मांगते, कचरा बीनते, जूते पॉलिश करते या कारखानों में सस्ते श्रमिक की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। बाल श्रम बच्चों को न केवल शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है बल्कि उन्हें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी हानि पहुंचाता है। अस्वच्छ और खतरनाक वातावरण में काम करने के कारण बच्चों को सांस की बीमारी, अस्थमा, त्वचा रोग, टीबी, रीढ़ की हड्डी के विकार और कैंसर तक हो सकता है। साथ ही लंबे समय तक पोषण की कमी और शारीरिक शोषण के कारण वे उम्र से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं और मानसिक रूप से भी अवसाद, डर, हीनता ग्रंथि और अपराध की दुनिया की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। यह समस्या सिर्फ मानवीय संकट नहीं है, यह आर्थिक और सामाजिक विकास में भी बाधा है। एक समाज का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। यदि वह पीढ़ी शिक्षा के बजाय बचपन में ही मजदूरी करने लग जाए तो न केवल उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति भी अवरुद्ध हो जाती है। मानव संसाधन की क्षति, उत्पादकता में गिरावट और सामाजिक असमानता जैसे दुष्परिणाम सामने आते हैं।

बाल श्रम के पीछे अनेक कारण हैं लेकिन गरीबी इसकी सबसे मजबूत जड़ है। जब एक परिवार अपनी बुनियादी आवश्यकताओं भोजन, पानी, दवा और शिक्षा को पूरा नहीं कर पाता तो बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेज देना मजबूरी बन जाती है। इसके अलावा निरक्षरता, कुपोषण, किसी सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का अभाव, बाल तस्करी और अज्ञानता भी बाल श्रम के प्रमुख कारक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों को यह तक पता नहीं होता कि उनके बच्चे को मजदूरी पर लगाना कानूनी अपराध है और संविधान उनके बच्चे को शिक्षा और सुरक्षित बचपन का अधिकार देता है। बाल श्रम को रोकने के लिए भारत में 'बाल श्रम (निषेध और

विनियमन) अधिनियम 1986' बनाया गया था, जिसे 2016 में संशोधित कर और कठोर किया गया।

इस संशोधन में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के किसी भी कार्य में नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है, साथ ही 14-18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक उद्योगों में काम पर लगाने पर भी रोक लगाई गई है। इसके बावजूद इस कानून की प्रभावशीलता संदिग्ध बनी हुई है क्योंकि निगरानी, प्रवर्तन और सजा की प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत कमजोर हैं। कई बार बच्चा 'परिवार की मदद' के नाम पर घरेलू उद्योगों में कार्य करता रहता है और कानून इसकी सही से व्याख्या नहीं कर पाता।

बाल श्रम से जुड़ी एक बड़ी विडंबना यह भी है कि कई बार इन्हें बचाने वाले कानून ही इनके अधिकारों की राह में बाधा बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब कानून में यह प्रावधान है कि बच्चा पारिवारिक काम कर सकता है तो इसका फायदा उठाकर बाल मजदूरी को पारिवारिक रोजगार बताकर उसे वैध ठहराने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्रों में, जहां निरीक्षण की व्यवस्था नहीं है, वहां तो स्थिति और भी भयावह होती है। भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना' जैसी योजनाएं भी चलाई हैं, जिनका उद्देश्य 9 से 14 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों को बचाकर उन्हें विशेष विद्यालयों में दाखिल कराना और उन्हें पुनर्वास सहायता देना है लेकिन इन योजनाओं का कार्यान्वयन और जमीनी असर आज भी सीमित और असमान है। कई जिलों में इनकीउपस्थिति नहीं है और जहां है भी, वहां संसाधनों और प्रशिक्षित मानवबल कीकमी है। यदि भारत को सच में बाल श्रम मुक्त बनाना है तो केवल कानून बनाना या कुछ योजनाएं शुरू करना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए व्यापक सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है। सबसे पहले तो सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे मूलभूत क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना होगा ताकि गरीब परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सक्षम बनें। साथ ही कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत बनाकर युवाओं को रोजगार योग्य बनाना होगा ताकि गरीबी का दुष्चक्र टूट सके। दूसरी ओर, समाज को भी बाल श्रम के खिलाफ एकजुट होना होगा। जब तक हम अपने आस-पास किसी ढाबे या कारखाने में बच्चों को काम करते देखते हुए चुप रहते हैं, तब तक इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। इस दिशा में नागरिक समाज, मीडिया और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें जमीनी स्तर पर बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने होंगे, लोगों को उनके अधिकारों और बच्चों की शिक्षा की महत्ता के बारे में बताना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्कूल, पंचायत, युवा क्लब, महिला संगठन, सब मिलकर बाल श्रम के खिलाफ एक सामूहिक प्रयास करें, तभी बात बनेगी। प्रौद्योगिकी के इस युग में अब आवश्यक हो गया है कि डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाए। सोशल मीडिया और मोबाइल एप्स के जरिये भी बाल श्रम की घटनाओं की रिपोर्टिंग को सुलभ और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसके अलावा, बच्चों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी देना और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत लाना बेहद जरूरी है। अंततः बाल श्रम केवल एक सामाजिक या कानूनी समस्या नहीं है, यह मानवता के खिलाफ एक अपराध है। जब तक एक भी बच्चा स्कूल के बजाय मजदूरी कर रहा है, तब तक हम एक सभ्य समाज कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। जिस दिन हर बच्चा पढ़ाई, खेल और स्वप्न देखने की आजादी महसूस करेगा, वही दिन होगा, जब भारत वास्तव में 'नया भारत' कहलाने योग्य बनेगा। हमें उस दिशा में आज ही, अभी से, पूरी ताकत और नीयत के साथ चलना होगा। यही हमारे बच्चों के प्रति सच्चा कर्तव्य और भविष्य के भारत के प्रति हमारी जिम्मेदारी है।

व्यक्तित्व

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

एक थे महाराजा किशन परसाद

मुझे लगभग यकीन है कि आप महाराजा किशन परसाद को नहीं जानते होंगे। हिन्दी जगत में बहुत बिरले होंगे जो उनसे वाकिफ होंगे। मैंने भी उन्हें बहुत देर से बीते बरस तब जाना, जब मैं शहरे-हैदराबाद पर एक किताब पढ़ रहा था। लेकिन उनहें जानकर मुझे लगा कि लोगों को उन्हें जानना चाहिये। वजह यह कि वह लासानी शख्सियत थे। वह सामंती रंगढंग में पली-बढ़ी शख्सियत थे। उम्दा प्रशासक थे। विविध कला रूपों उनकी गहरी रूचि थी। वह शाइर थे। एडीटर थे। गंगो-जमुनी तहजीब की मौजें उनके व्यक्तित्व में हिलोर लेती थीं। वह नेक दिल थे और आडंबर से कोसों दूर। वह सूफी परंपरा में यकीन रखते थे और वह अपने जीवन में ऐसा कुछ कर गुजरे कि उनकी जिंगदी अनूठी नज़ीर हो गयी। महाराजा सर किशन परसाद बहादुर यामीन-उस-सल्तनत का जन्म हैदराबाद में सन 1864 में साल के पहले दिन हुआ था। उनके जन्म की वास्तविक तारीख को लेकर विवाद है। बहरहाल वह कुलीन घराने के थे और दो बए हैदराबाद के प्रधानमंत्री रहे। वह निजाम के बालपने के साथी थे और आजीवन उनके विश्वास-पात्र और वफादार रहे। उनका पहला कार्यकाल सन 1901 से 11 जुलाई सन 1911 के दरमन रहा, जब मूसी नदी में प्रलंयकारी बाढ़ आई। असल में परशाद की निजाम की खिदमत का सिलसिला सन 1892 से शुरू हुआ, जब वह रियासत के पेशकार बनाये गये। अपनी काबलियत से उन्होंने निजाम महबूब अली खान का ध्यान खींचा और उन्होंने उन्हें नौ साल बाद रियासत का दीवान बना दिया। दीवान बनते ही उन्होंने रियासत के राजस्व को बढ़ाने का बीड़ा उठाया और इसमें कामयाब भी हुये। उनके दीवानी काल में आय चौगुनी बढ़ी। अपने इसी काल में हैदराबाद को अभूतपूर्व प्राकृतिक विपदा का सामना करना पड़ा। 28 सितंबर, 1908 को मूसी नदी के तटबंध तोड़ दिये। इस बाढ़ ने करीब 15000 लोगों की जानें लील लीं। हजारों लोग बेघर हुये। साढ़े बारह लाख पौण्ड से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ। स्थानीय बोली में ठगयानी सीतांबर नामक इस आपदा ने तीन पुलों-अफजल, मुसल्लम जंग और चदरघाट को बहा दिया। केवल पुराना पुल की मार्फत शहर के दोनों हिस्सों में आवाजाही बनी रही। नदी का ऊान कई फुट ऊपर उठा और उसने शहर कें हहाकार मचा दिया। अफजलगंज में में जल स्तर 11 फुट ऊपर था और अन्यत्र जल स्तर और भी अधिक। बादल फटने से विभीषिका और बढ़ गयी। 36 घंटों में 17 इंच बारिश दर्ज की गयी। कोलसावाड़ी और घांसी में तो त्राहि-त्राहि का आलम था। विभीषिका ऐसी थी कि करीबन चौथाई आबादी बेघर थी। उस्मानिया अस्पताल के आहाते में वह इमली का दरख्त आज भी मौजूद है, जिस पर चढ़कर डेढ़ सौ साल से ज्यादा लोगों ने जान बचाई थी। शाइर अमजद हैदराबादी का पूरा परिवार बह गया और उन्होंने अपने विषाद और अवसाद को 'कयामत-ए-सोगरा' की रूबाइयों में व्यक्त किया।

दीवान किशन परसाद के यि यह परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने मुस्तैदी से सामना किया। निजाम आसफजाह षष्ठम सर महबूब अली खान ने पांच लाख रूपये का जो राहत कोष बनाया, उसमें सबसे बड़ा योगदान किशन परसाद का था। महल के दरवाजे शरण के लिये खोल दिये गये। राहत के लिये हाथी-घोडों के लश्कर लगाये गये। दस दिन अवकाश रहा। शहर में दस रसोइयां खोली गयी। एक बड़ी घटना यह घटी कि दीवान और दरबारी ज्योतिषी झूमरलाल तिवारी की सलाह पर निजाम महबूब अली ने धोती-जनेऊ पहना और मूसी नदी को शांत करने के लिये फल-फूल, नारियल, रेशमी साड़ी, मोती और सोने के साथ हिन्दु विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। यह नदियों को मां मानने की परिपाटी के अनुरूप था। एक मुस्लिम शासक का हिन्दु-अनुष्ठान उनके आदार्य और प्रजा वत्सल चरित्र को दर्शाता है।

तो ऐसे थे दीवान किशन परसाद। बाढ़-राहत के लिये जो दस लाख रूपयों की राशि सार्वजनिक सहायता से जुटायी गयी, उसमें किशन प्रसाद का निजी योगदान और अथक प्रयास अतुल्य था। इस बाढ़ और उसके प्रबंधन ने भावी सुधारों औरनिर्माणों की नींव रखी। जांच कमेटी का गठन हुआ, हैदराबाद इंप्रूव ट्रस्ट बना और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जैसे शीर्षस्थ इंजीनियर को आमंत्रित किया गया। फलस्वरूप कतिपय बांधों का निर्माण हुआ, जो आज भी हैदराबाद की सुरक्षा और पेयजल आपूर्ति के साधन हैं।

महाराजा किशन परसाद का शजरा प्रभावशाली है। वह भटनागर कायस्थ थे। उनका ताल्लुक चंदूलाल शादां के घराने से था। उनके पुरखा राय मूलचंद आसफ ज़ाह प्रथम के साथ दिल्ली से हैदराबाद आये थे। उनके दादा नरिंदर प्रसाद महबूब अली खां के काल में दीवान और पेशकार रहे। जाहिर है कि किशन प्रसाद को संपाम विरासत मिली थी, लेकिन दादा नरिंदर न जाने किसा बात पर खफा हुये कि उन्होंने किशन को उसके छोटे भाई के पक्ष विरासत से वंचित कर दिया, मगर किशन परसाद की खुशनसीबी कि उन्हें सालार गंज प्रथम का संरक्षण मिला, लिहाजा जंग परिवार के नौनिहालों के साथ पश्चिमी ढब के स्कूलों में उकनी शिक्षा-दीक्षा हुई। उन्होंने लेखाशास्त्र, धर्म, ज्योतिष, औषधि, सूफीवाद और संस्कृत में अध्ययन किया। उन्होंने मार्शल आर्ट, दरबारी रीति-रिवाज और मुगल शिष्टाचार भी सीखा। उनके परिवार के पास शाही खजाने का वंशानुगत प्रभार होना मायने रखता था। सन 1901 में निजाम ने विकार-उल-उमरा को बर्खास्त कर किशन परसाद को रियासत का

दीवान बना दिया। साथ ही उन्हें यामिन-उस-सल्तनत की उपाधि से नवाजा गया, जिसके मानी थे सल्तनत का दायां बाजू। उनका दर्जा भी राजा से बढ़कर महाराजा हो गया किशन परसाद ने बतौर दीवान ताबड़तोड़ कदम उठाये और मनसबदारों की आय घटाने के साथ ही कृषि, रेलवे और सीमा शुल्क में बढ़ोत्तरी की। नतीजतन राजस्व खूब बढ़ा। इसका श्रेय वजीरें खजाना कैसन वाकर को भी दिया जाता है, अलबत्ता निजाम ने अपने दीवान की पीठ थपथपायी। रियासत मालामाल हुई। बहरहाल, सन् 1911 में महबूब अली के उपरांत उस्मान अली खान सिंहासनारूढ़ हुये तो किशन परसाद को अड़चनों का सामना करना पड़ा। फलतः उन्होंने दीवान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। किशन परसाद को बतौर दीवान दूसरी पारी खेलने का मौका बीसवीं सदी की तीसरी दहाई में मिला। नवंबर, 1926 में वह पुनः दीवान बनाये गये और इसस पद पर मार्च, 1937 तक रहे। कैसन वाकर से उनका इस काल में भी टकराव हुआ। वाकर जहां प्रशासनिक पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति का पक्षधर था, किशन परसाद मुल्कियों यानि स्थानीयों की नियुक्ति के हिमायती थे। वाकर और परशाद में टकराव चिंता का सबब था, लेकिन किशन परशाद मुल्की कानून पारित कराने में सफल रहे। इसके तहत प्रशासनिक पदों पर गोरों के बजाय योग्य और अनुभवी होने पर स्थानीय जनों की नियुक्ति होनी थी। इसी क्रम में सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष तय की गयी। किशन परशाद की एक खूबी यह भी थी कि उन्होंने ब्रिटिश रेजीडेंट से संबंध लगातार अच्छे बनाये रखे।

किशन परशाद का जीवन बड़ा दिलचस्प रहा। वह रसिक मिजाज शख्सियत थे। उनकी सात पत्नियां थीं; तीन हिन्दु और चार मुस्लिम। इनमें एक शिया मतावलंबी भी थी। मुस्लिम बीवियों से उन्हें छह और हिन्दु पत्नियों से नौ संताने हुई। सभी पत्नियों को अपने-अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता थी और संतानों का पालन-पोषण उनकी मांओं के धर्म के अनुरूप हुआ। उनका सेक्यूलर मिजाज देखिये कि मुस्लिम बच्चों के नाम मुस्लिम और हिन्दु बच्चों के नाम हिन्दु परंपरानुसार रखे गये।

किशन परशाद के वैवाहिक-प्रसंगों से जुड़ा रोचक क्षेपक है। परशाद की एक प्रिय पत्नी थी गौसिया बेगम। गौसिया रूढ़िवादी मुस्लिम खानदान से थी। परशाद उन्हें बेतरह चाहते थे। दिक्कत थी कि मिलाप और शादी कैसे हो। परशाद भेष बदलकर अनेकश-मिले और उन्हें रजामंद करने में कामयाब रहे। मगर एक मुस्लिम खातून का गैर-मुस्लिम से निकाह कैसे हो? मोहब्बत ऐसी कि परशाद धर्म-परिवर्तन को तत्पर हो गयी। तब निजाम महबूब आड़े आये। वह नहीं चाहते थे कि परशाद कलमा पढ़ें। वह हिन्दु बहुल रियासत के सर्वेसर्वा थे। उनकी मंशा थी कि रियासत के दीवान व पेशकार का हिन्दु होना श्रेयस्कर होगा। अंततः उनकी युक्ति कारगर रही।

किशन परशाद की अदब में गहरी रूचि थी। उनका पेंटिंग, संगीत और मूर्ति कला से भी गहरा लगाव था। उनके यहां फनकारों का तांता लगा रहता था। दूर फारस और अरब देशों से फनकार आते जाते थे। परशाद स्वयं 'शाद' उपनाम से उर्दू और फारसी में पद्य लिखते थे। सूफी वाद उनकी रगों में था और गंगो-जमुनी तहजीब उनका मिजाज थे। उन्होंने 'महबू-अज-कलाम' नामक उर्दू कविता का रिसाला भी निकाला। इसमें पहली गजल निजाम महबूब अली खां की थी और बाद की रचानाएं परशाद की। गजलें दो प्रेमियों के बीच कथोपकथन की शैली में थीं। एक ठौर उन्होंने लिखा ङ्क=मैं न तो हिन्दु हूँ/न ही मुसलमान हूं/मेरा विश्वार हर धर्म में है। केवल शाद ही अपने धार्मिक विश्वास को जानता है क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति के अलावा/कोई भी स्वतंत्रता का सार नहीं समझ सकता। 'किशन परशाद सही अर्थों में हरफनमौला शख्सियत थे। वह कद्रदां थे। वह फोटोग्राफी करते थे और सितार भी बजाते थे। वह दानी प्रवृत्ति के थे। उनके घर के दरवाजे अमीर-गरीब सबके लिये खुले रहते थे। यहां तक कि वह किसी भिखारी के साथ भी सोफे पर बैठ चाय पी लिया करते थे। वह टोकने पर कहते-'न जाने किस भेष में नारायण मिल जाये। वह शादी-ब्याह के जलसों में शरीक होते, स्कूलों-कॉलेजों उदघाटन और समारोहों में जाते और बतौर चीफ गेस्ट सर्कस में भी चले जाते थे। सन 1903 में उन्हें केसीआईआई और सन 1910 में जीसीआई की पदवियां दी गयी। 4 फरवरी 1936 को उनकी नयी ड्योढ़ी की नींव रखी गयी। इस ड्योढ़ी के वास्तुकार थे मोहम्मद फयाजुद्दीन। 13 मई 1940 को उन्होंने फानी संसार को अलविदा कह दिया। निजाम उस्मान ने कहा - 'समाज ने मुगल साम्राज्य के अंतिम निशान को खत्म होते देखा है।' टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके बारे में कहा - 'उनके करिश्माई व्यक्तित्व और महान उदारता ने उन्हें जनता का प्रिय बना दिया। तत्कालीन हैदराबाद में सभी अच्छाइयों के सर्वोच्च सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने यह सुनिश्चित किया कि महाराजा का अर्थ कोई और नहीं, बल्कि किशन परसाद है।'

संस्मरण

सुरेंद्र दांगी

परशुराम मामा, राम और भोला

वे हमारे मामा के यहाँ हाली थे। खेती के सभी कामों के साथ-साथ पालतू पशुओं की देखभाल करना भी उन्हीं के जिम्मे था। वे अकेले थे। गरीबी के कारण शादी भी नहीं हुई थी। मामा के दिये हुए मकान में वे रहते थे। खाना स्वयं बनाते थे। बीड़ी पीने के अलावा अन्य कोई भी व्यसन उनमें नहीं था। उम्र होगी 35-40 साल के लगभग। सांवला रंग बलिष्ठ शरीर के धनी खूब मेहनती आदमी थे। बड़ी-बड़ी मूंछे चाय-दूध पीते वक्त छन्नी का काम करती थीं। गरीब होने के बावजूद गले में सोने का हल्का ताबीज़ और एक कान में 3 आना भर की बारी पहनते थे। कुल जमा सम्पत्ति के नाम पर यही कुछ उनके पास था। उनके घर-परिवार में शायद कोई नहीं था। कमीज़ और धोती में वे सुदर्शन दिखते थे।

उन्हीं दिनों मामा की गाय ने बछड़ा जना। जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से 'राम' रखा। राम के लालन-पालन का उन्होंने विशेष ध्यान रखा। राम उनके लिये जैसे जीवन का आधार ही बन गया। वे गाय के दो थनों को ही दुहते। दो थन राम के लिये छोड़ देते। राम का रंग एक दम सफेद था, माथे के बीच लाल रंग का निशान उसकी खूबसूरती में वृद्धि करता था। बड़ी-बड़ी आंखे। देखने में बहुत प्यारा था राम। वे राम के साथ खेलते बतियाते रहते थे। राम ही एक तरह से उनका एक मात्र परम आत्मीय था। राम उनके एकरंगी एकांकी जीवन का सहयोगी बन गया था। वे उसे अपना बेटा कहते थे।

भोला उस सांड का नाम था जिसे गाँव वालों ने त्रिशूल दाग कर छोड़ा था। भोला जिसके खेत में चाहे चरता था। उसे

कोई रोक टोक न थी। गाँव वालों का यह घोषित नियम था कि भोला को कोई खेत से नहीं भगाएगा। भोला दिन भर दलांकता रहता और गांव भर के घूरे अपने सींगों से उलीचता फिरता था। दरअसल, भोला देहाती समाज की उस परम्परा के तहत छोड़ा गया था जिससे गाँव भर की गायें 'फलतीं' रहें। जिस काम के लिये भोला को छोड़ा गया था उस काम को करने में भोला ने कोई कोताही ही नहीं बरती थी। परशुराम मामा (परम्परा के नाते मैं उन्हें मामा ही कहता था) के 'राम' का पिता भी यही भोला था।

गर्मियों की मेरी छुट्टियां मामा के यहाँ ही बीतती थीं। समय के साथ राम भी बड़ा हो गया। उस पर भी जवानी आई। वह भी थोड़ा-थोड़ा भोला जैसा दिखने लगा। वह भी भोला को देखकर दलांकता, खुरी करता अपने सींगों से मिट्टी उलीचता। भोला को उसमें अपना भावी प्रतिद्वंद्वी दिखाई देने लगा। लेकिन अभी तक उनमें सीधी भिड़ंत नहीं हुई थी।

उस साल भी गर्मियों में मैं मामा के यहाँ ही था। गाँव वाले अपने घरों पर छाने के लिए 'खपरे' (कवेलू) स्वयं बनाते थे। और उन्हें पकाने के लिये आवा (आंवा) गांव के नजदीक खेड़ों में लगाते थे। उन दिनों जगह-जगह खपरे पक रहे थे। दहकते आवों के पास ही नीम के पेड़ की छाँव में भोला कई गायों से घिरा खड़ा हुआ था। तभी राम का गुजरना वहाँ से हुआ। भोला ने बिना वजह ही राम को खदेड़ दिया। जवान राम को इसमें अपना अपमान लगा। वह दलांकता हुआ खुरी करने लगा। पास की मिट्टी में सींग गड़ाकर उसे उलीचा। भोला को लगा कि राम उसे चुनौती दे रहा है। वह अब बूढ़ा हो चला था लेकिन अपने 'राज' में किसी का भी वर्चस्व स्वीकार न था। देखते ही देखते राम और भोला आपस में भिड़ गए। पलक झपकते यह खबर गाँव भर में फैल गई। लगभग पूरा गांव इस लड़ाई को देखने घटना स्थल पर एकत्र हो गया।

टक्कर लगभग बराबर की थी। कभी भोला जीतता दिखता तो कभी राम। भोला बूढ़ा जरूर था लेकिन अनुभवी था। राम जवान था लेकिन अनुभव की कमी थी। गाँव भर के लोग शोर मचा रहे थे। कुछ समझदार लोग दोनों को अलग करने के लिये भी प्रयासरत थे। तभी भोला जोर से दलांकता हुआ राम को धकियाता गया और सिर का ऐसा बार किया कि राम उछलकर धधकते हुए आवा में गिर गया। पूरा गांव दौड़ पड़ा लेकिन आग बहुत तेज थी। गांव वालों ने जितनी जल्दी हो सकता था राम को आवा से निकाल लिया। लेकिन इतनी देर में राम बुरी तरह से झुलस गया था। परशुराम मामा भी तब तक आ गए थे।

पास के दालान में राम को लिटा दिया गया। उन दिनों पशुओं की चिकित्सा की कोई व्यवस्था न थी। परशुराम मामा का रो-रो कर बुरा हाल था। जलने पर देसी इलाज़ जिसने भी जो बताया वह मामा ने किया। देवस्थानों पर जाकर भभूत भी लाये और गुनियाँ-ओझाओं से झाड़फूंक भी करवाई। कहावत है जिसका ऊँट खो जाए वह उसे गागर में भी खोजता है। राम की देखभाल उन्होंने बिल्कुल वैसे ही कि जैसे कोई अपने आत्मीयजन की करता। वे सारे काम छोड़कर राम की सेवा में लगे रहे। राम कुछ ज्यादा ही जल गया था। लगभग 15-20 दिन की सेवा के बाद राम, राम को प्यारा हो गया। परशुराम मामा का दिल टूट गया। एक दिन बिना बताए उन्होंने गाँव छोड़ दिया। रामजाने वे कहाँ गए।

हाईवे के ढाबे बने अवैध शराब व्यापार के अड्डे

- बेच नंबर मिलान के बाद ठेकेदार पर भी होगी कार्रवाई

बैतूल/मुलताई। नेशनल हाईवे मुलताई के ढाबे जुआ, सट्टे के साथ ही अवैध शराब व्यापार के अड्डे बनते जा रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने मासोद रोड से एक कार से 196 लीटर 56 मिली अवैध देशी शराब जप्त की जिसका मूल्य 110220 रुपए है। पुलिस को देख कार क्रमांक एमपी 48 सी 6426 चालक एवं ढाबा संचालक और उसका सहयोगी फरार होने में सफल हो गए थे। इस मामले में मुलताई पुलिस ने ढाबा संचालक के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर उसकी एवं सहयोगी की तलाश प्रारंभ कर दी है। थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया ने बताया कि अवैध शराब के मामले में मोंटी पवार एवं उसकी सहयोगी अभी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। मारुति सुजुकी कार से बड़ी मात्रा में प्लेन शराब बरामद हुई थी जिसके बैच नंबर के आधार पर आबकारी अधिकारियों को लिखा गया है। बेच नंबर का मिलान करने के बाद ठेकेदार की पुष्टि होने पर ठेकेदार पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिस कार से शराब का परिवहन किया गया था, उसके राजसात की कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है। पुलिस आरोपी और उसके सहयोगी की सरगर्मी से तलाश कर रही है शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहां उल्लेखनीय है कि हाईवे से लगे ढाबों से अवैध शराब एवं अवैध गतिविधियों के संचालन की निरंतर खबरें आती रही है किंतु शराब का यह जखीरा मिलने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है और पुलिस भी अब इन ढाबो पर निगाह बनाए हुए हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या आने वाले समय में पुलिस को और बड़ी सफलता मिल पाती है अथवा नहीं। जानकार बताते हैं कि विशेष तौर से अवैध शराब एवं ब्रांडेड कंपनियों की नकली शराब का जो कारोबार संपूर्ण क्षेत्र में फैल रहा है यह चिंता का विषय है।

आई कैंप संपन्न, 35 मरीजों की निःशुल्क जांच

चिन्हित मरीजों का होगा निःशुल्क ऑपरेशन

बैतूल। वरिष्ठ नागरिक संगठन के तत्वावधान में वन ग्राम रैयतवाड़ी में निःशुल्क आई कैंप संपन्न हुआ। शिविर में बैतूल के विजन सेंटर में डॉ.पीके वर्मा ने 35 आदिवासी मरीजों के मोतियाबिंद की जांच की। कैम्प में संगठन के श्री गलफट, नरेन्द्र दीक्षित, अरूण यादव, श्रीमती शुभा आदि मौजूद थे। आगामी आई कैम्प 14 जून को मर्दवानी के पंचायत भवन में, 15 जून को मोहपानी के वन विश्राम गृह में और 16 जून को बैतूल गंज के सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय में होगा। सभी चिन्हित मरीजों को 16 जून को चिकित्सालय की एंबुलेंस बस से भोपाल भेजा जाएगा। जहां 17 जून को मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाएंगे। संगठन ने बताया कि चिन्हित मरीज अपने साथ आधार कार्ड और मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति का लाना आवश्यक होगा।

जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे रेत, गिट्टी, मुरुम के अवैध भंडारण एवं परिवहन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत खनिज विभाग द्वारा जिले के अलग-अलग स्थानों पर विगत चार दिवसों में लगातार बड़ी कार्यवाही की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 जून को रेलवे कंपनी द्वारा बिना अनुमति के रेत और गिट्टी खनिजों के अवैध भंडारण किए जाने की शिकायत पर संयुक्त रूप से खनिज एवं राजस्व अमले के द्वारा ग्राम पंचायत मरामझिरी के सरपंच एवं भूमि स्वामी की उपस्थिति में भंडारण स्थल की जांच की गई। मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम मरामझिरी स्थित निजी भूमि खसरा क्रमांक 03 रकबा 1.032 हेक्टेयर के अंश भाग पर रेलवे कंपनी द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से रेत एवं गिट्टी का भंडारण किया गया था। मौके पर रेत की मात्रा 3722 घन मीटर और गिट्टी की कुल मात्रा 5727 घन मीटर पाई गई। मौके पर उपस्थित एनपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रेलवे कंपनी में कार्यरत श्री नंदकिशोर राठौर द्वारा बताया गया कि कंपनी के द्वारा रेलवे की तीसरी लाइन में मरामझिरी से धाराखोह का निर्माण कार्य किया जा रहा है एवं उक्त कार्य के लिए खनिज रेत एवं गिट्टी के भंडारण की कोई अनुमति नहीं ली गई है। उक्त खनिज मात्रा को जब्त कर अवैध भंडारण कर्ता के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत कुल शास्ति की राशि 3 करोड़ 45 लाख 74 हजार 700 रूपए प्रस्तावित किया जाकर प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा 9 जून को खनिज अमले ने बिना रॉयल्टी के मुरुम के अवैध परिवहन करते हुए एक डंपर क्रमांक एमपी 48 एच 1063 को खेड़ी सावली गढ़ के पास जप्त किया गया। जिसे पुलिस की अभिरक्षा में खड़ा किया गया है।

दो मंदिर, एक मदरसा और तीन पक्के मकानों पर चला बुलडोजर

पुराने अस्पताल की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई

बैतूल/मूलताई। मुलताई नगर प्रशासन ने आज पुराने स्वास्थ्य केंद्र की पौन एकड़ भूमि से वर्षों पुराना अतिक्रमण सख्ती के साथ हटा दिया। भारी पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में 1986 से संचालित मदरसे को जेसीबी एवं पोकलेडं मशीनो द्वारा तोड़कर समतल कर दिया गया, इसके साथ ही दो छोटे मंदिर शंकर मंदिर एवं दुर्गा मंदिर को भी अतिक्रमण हटाओ मुहिम की भेंट चढ़ना पड़ा। इस भूमि पर तीन पक्के मकान बना लिए गए थे, महिलाओं के भारी विरोध के बावजूद कुसुम नागले, कलश बेले, जसवंती बाई का मकान तोड़ दिया। अतिक्रमण हटाने की यह मुहिम सुबह से प्रारंभ कर दी गई थी। सुबह लगभग 8 बजे तीन जेसीबी एक पोकलेन मशीन, कइयों ट्रैक्टर ट्राली के साथ महिला पुलिस बल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई अनीता पटेल, एसडीओ मुलताई पुलिस ए.के. सिंह दर्जनों पुलिसकर्मी, तहसीलदार और पटवारियों का दल जामा मस्जिद के सामने स्थित पुराने अस्पताल की भूमि, जो कि नया अस्पताल बन जाने के बाद खाली हो गई थी, पर पहुंचे और उससे पहले की कोई कुछ समझ पाता, अतिक्रमण हटाने की मुहिम प्रारंभ कर दी गई।

अतिक्रमण हटाने को लोगों ने बताया अनुचित कार्यवाही: अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को महिलाओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जिन महिलाओं के मकान तोड़े गए, उन लोगों का आरोप था कि प्रशासन ने उन्हें समय रहते नोटिस नहीं दिया और अब अचानक आकर उन्हें सामान निकालने का भी अवसर नहीं दे रहे हैं और संपूर्ण मकान को तोड़ दिया गया है जो कि अनुचित है। इस बीच एक महिला एवं महिला पुलिसकर्मियों के बीच झूमा झटकी भी हुई। एक महिला ने महिला कर्मियों पर पत्थर उठा लिया था। इधर दूसरी ओर वर्षों पुराने उर्दू मदरसे को हटाए जाने को लेकर समुदाय विशेष में भारी रोष है। हाजी शमीम खान वक्फ बोर्ड जिला अध्यक्ष ने प्रशासन की इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कहा है कि यहां वर्षों से मदरसा चल रहा है, जहां बच्चे तालीम पाते रहे हैं। शासन ने मदरसा संचालन के लिए यह भूमि विधिवत लीज पर दी थी, जो कि अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आती।

गीता भवन निर्माण के लिए हटाया गया अतिक्रमण

मध्यप्रदेश सरकार संपूर्ण प्रदेश में नगर पालिका क्षेत्र में 413 गीता भवन निर्माण करने जा रही है। उक्त भूमि का चयन पवित्र नगरी मुलताई में गीता भवन निर्माण के लिए किया गया है। हालांकि गीता भवन निर्माण के लिए लगने वाली भूमि की तुलना में उक्त भूमि बहुत ज्यादा है, और शेष भूमि का नगर पालिका अन्य व्यावसायिक उपयोग भी कर सकती है। नगर पालिका मुलताई के राजस्व निरीक्षक जीआर देशमुख ने उक्त पुष्टि करते हुए बताया कि नगरीय क्षेत्र में बनने वाले प्रस्तावित गीता भवन निर्माण के लिए उक्त स्थल को खाली कराया जा रहा है ताकि गीता भवन निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

इनका कहना है -

राजस्व, पुलिस और नगर पालिका की टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और फिर से अतिक्रमण न हो, इसके लिए संपूर्ण भूमि की फेंसिंग का कार्य भी किया जा रहा है।

-अनीता पटेल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुलताई

बैतूल में 13 से 15 जून तक चलेगा महिला पतंजलि योग समिति का आवासीय शिविर

महिलाओं को सशक्त बनाएगा राज्य स्तरीय महिला योग शिविर

बैतूल। महिला पतंजलि योग समिति बैतूल के तत्वावधान में आगामी 13, 14 और 15 जून को राज्य स्तरीय आवासीय महिला योग कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला बैतूल जिले के रामाश्रय अवस्थी कॉम्प्लेक्स, रानीपुर रोड स्थित जिला कार्यालय में आयोजित होगी। कार्यशाला का समय प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस आयोजन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं और इसके लिए जिले के सभी कार्यकर्ताओं को पूर्व में सूचना दे दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए समिति की प्रमुख श्रीमती संगीता अवस्थी ने बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर बैठकें आयोजित कर रूपरेखा तैयार की गई है और सभी कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। महिला पतंजलि योग समिति की ओर से यह अपील की गई है कि राज्य एवं जिले की सभी महिला कार्यकर्ता बहनों से इस कार्यशाला में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें।

इस राज्य स्तरीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिला कार्यकर्ताओं के योग, संगठन और नेतृत्व कौशल को सशक्त बनाना है। कार्यशाला में योग गुरु स्वामी रामदेव जी की परम शिष्या साध्वी देवादिती जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी और तीनों दिन अपने मार्गदर्शन में विविध सत्रों का संचालन करेंगी।

कार्यशाला की दिनचर्या इस प्रकार रहेगी: 13 जून को प्रातः 5:30 बजे से योग सत्र प्रारंभ होगा। इसके बाद चाय-नाश्ता, आध्यात्मिक चर्चा और विशेष बौद्धिक सत्र होंगे। दोपहर में भोजन व विश्राम के पश्चात फिर से आध्यात्मिक चर्चा, चाय-संवाद और शाम को साध्वी जी के साथ योग सत्र होगा। रात्रि में भोजन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। 14 जून को दिन की शुरुआत साध्वी जी के साथ योग सत्र से होगी। इसके बाद पूरे दिन आध्यात्मिक विषयों पर संवाद और अभ्यास सत्र चलेंगे। दोपहर के समय ग्रुप फोटो सेशन रखा गया है, जिसमें प्रतिभागियों को सफेद सलवार-कुर्ता, दुपट्टा अथवा साड़ी व जैकेट (यूनिफॉर्म) में रहना होगा। शाम को यज्ञ विषय पर चर्चा और रात्रि में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। 15 जून को कार्यशाला के अंतिम दिन सुबह योग सत्र के बाद चाय-नाश्ता होगा। इसके बाद प्रातः 9:30 बजे से 12 बजे तक समापन सत्र में यज्ञ आयोजन किया जाएगा।

आवास की व्यवस्था केवल बाहर से आने वाली महिलाओं के लिए की गई है। आयोजन को लेकर समिति के सभी कार्यकर्ता सक्रिय हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महिला पतंजलि योग समिति ने सभी महिला योग साधिकाओं, कार्यकर्ताओं और बहनों से इस शिविर में सहभागी बनने का आह्वान किया है ताकि संगठनात्मक और व्यक्तिगत उन्नति की दिशा में एक सशक्त कदम बढ़ाया जा सके।

बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश की बौछारें

बैतूल। बुधवार को दोपहर में अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। जिससे लोगों को तेज तपन और गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन चंद मिनटों के बाद ही बारिश थम गई। जिससे मौसम में उमस का माहौल बना रहा। दरअसल बुधवार दोपहर बाद आसमान में बादल छा गए हैं। तेज हवाएं चली और बारिश की बौछारे पडने़ लगी। जिससे तापमान में कुछ कमी दर्ज की गई। मंगलवार की तुलना में बुधवार के तापमान में 0.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को जून में पहली बार तापमान 40.2 डिग्री तक पहुंचा था। सोमवार को यह 39.5 डिग्री था। रात का तापमान भी 27 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मई में चक्रवात के कारण बादल और बारिश से लोगों को राहत मिली थी। लेकिन जून लगते ही तापमान बढने़ लगा था। मंगलवार को तापमान 40.2 डिग्री तक पहुंच गया था। वहीं बुधवार को तापमान 39.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में बने चक्रवातीय हवा के घेरे से गर्म हवा मध्यप्रदेश की ओर आ रही है। पिछले साल जिले में 9 जून 2024 को एक घंटे तक बारिश हुई थी। इसके कारण मौसम ठंडा हो गया था। हालांकि पिछले साल तापमान 39.5 डिग्री तक ही पहुंचा था, वहीं इस साल नौतपा पर भी चक्रवात का असर रहने से तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के अधिक नहीं गया, लेकिन बीते तीन दिनों से जून में तापमान हर दिन एक डिग्री बढ़ रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ससुंद्रा के इंटीग्रेटेड हेल्थ कैम्प में 78 हितग्राही हुए लाभान्वित

बैतूल। मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज हुरमाडे, जिला नोडल अधिकारी डॉ आनंद मालवीय के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड हेल्थ केम्प प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ससुंद्रा जिला बैतूल में आयोजित किया गया। हेल्थ केम्प में ब्लड शुगर, बीपी, एचआईवी, सिफिलिस, टीबी एवं हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग की गई एवं चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। काउंसलर सह डाटा मैनेजर श्री दिनेश भावरकर द्वारा ग्रुप काउन्सलिंग कर एचआईव्ही एवं एड्स, एसटीआई, हेपेटाइटिस एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की गई। पोस्टर और लीफलेट के माध्यम से आमजन को जागरूक किया गया और आईईसी के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की गई। उच्च जोखिम अवस्था वाले हितग्राहियों को सिविल अस्पताल आमला एवं जिला चिकित्सालय बैतूल रैफर किया गया, ताकि उन्हें आगे की जांच और उपचार के लिए आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। हेल्थ केम्प में 78 हितग्राही लाभान्वित हुए। शिविर में मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ अशोक नरवरे, काउंसलर सह डाटा मैनेजर दिनेश भावरकर, बीपीएम रमेश बिहारे, आईसीटीसी काउंसलर श्रीमती अनीता लोखंडे, अरुण वाघमारे, सुपरवाइजर सुभाष चंद्र गुजरकर, सीएचओ श्रीमती लक्ष्मी पवार, लैब टेक्नीशियन गणेश साकरे एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं जनसमुदाय मौजूद रहा।

केन्द्रीय मंत्री, बैतूल विधायक ने किया चौक-चौराहों के चौड़ीकरण-सौंदर्यीकरण का भूमिपूजन

514.34 लाख रुपये की लागत से होगा कार्य

बैतूल। शहर के आठ चौक-चौराहे को विकसित करने का काम मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें चौक-चौराहों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अलावा गांधी चौक पर पार्किंग सहित अन्य विभिन्न कार्य शहर में होगे। जिससे आने वाले समय में शहर सुव्यवस्थित एवं विकसित होगा। सड़कें सुगम हो और व्यवस्थित हो, इसकी और भी ध्यान दिया जाएगा। यह बातें बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने बुधवार को शहर के चौक-चौराहों के सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण के भूमिपूजन कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहीं। इस दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री डीडी उइके, नपाध्यक्ष बैतूल पार्वतीबाई बारस्कर, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार, पूर्व विधायक अलकेश आर्य, नपा उपाध्यक्ष महेश राठौर, पार्षदगण में नपा नेता प्रतिपक्ष राजकुमार दीवान, रघुनाथ लोखंडे, पवन यादव, ममता मालवी, रजनी वर्मा, नंदिनी तिवारी आदि की मौजूदगी में शिवाजी चौक, अंबेडकर चौक एवं कारगिल चौक-चौराहों का भूमिपूजन किया गया। इस अवसर पर बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी हो या नगरपालिका, सभी के सहयोग से शहर को विकसित करने का काम किया जायेगा। कारगिल चौक से गड़ाघाट वाली सड़क के लिए भी पीडब्ल्यूडी को 7 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है। इस सडक का भी जल्द ही भूमिपूजन किया जायेगा। यह रोड बैतूल की सबसे व्यस्ततम सडक में से एक है, इसलिए इसका चौड़ीकरण भी किया जायेगा और बिजली पोल शिफ्ट किया जायेगा। कारगिल चौक से सदर को भी जोडने़ का काम शीघ्र किया जायेगा। बता दे कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजनान्तर्गत शहर के विभिन्न चौराहों के सौंदर्यीकरण एवं पार्किंग निर्माण कार्य किया जाना है।

इस योजना की कुल लागत 514.34 लाख रुपये है, जिसके लिए विधायक हेमंत खंडेलवाल के निरंतर प्रयासों और शासन स्तर पर की गई पैरवी के परिणामस्वरूप यह स्वीकृति प्राप्त हुई है। बुधवार की शाम 5 बजे शहर के शिवाजी चौक, अंबेडकर चौक और कारगिल चौक पर भूमिपूजन किया गया। इन तीनों प्रमुख चौराहों पर सौंदर्यीकरण के साथ-साथ पार्किंग निर्माण जैसे आवश्यक कार्य किए जाएंगे, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और चौराहा का सौंदर्य भी निखरेगा। इस योजना से बैतूल शहर का सौंदर्य और सुव्यवस्था दोनों ही बेहतर होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री का माना आभार

- भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दी मान्यता

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज विस्तार को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मान्यता देने पर नागरिकों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर कहा कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत की उल्लेखनीय वृद्धि केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सार्वजनिक सेवा और समावेशी विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का शानदार उदाहरण है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने और हर नागरिक को सम्मान के साथ मुख्य धारा में शामिल करने के हमारे संकल्प को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समाज के हर वर्ग के कल्याण और सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी दूरदर्शी सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए निर्धन-केंद्रित और श्रमिक कल्याण योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ-सबका विकास' के विजन से प्रेरित होकर भारत ने समाजिक सुरक्षा कवरेज के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जो वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण विस्तारों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के आईएलओ स्टेट डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा करवरेज 2015 में 19 प्रतिशत था, जो 2025 में बढ़कर 64.3 प्रतिशत हो गया है। लाभार्थियों की संख्या के मामले में भारत अब विश्व में दूसरे स्थान पर है, जो 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान कर रहा है।

दो मीडिया एंकर गिरफ्तार

नोएडा। नोएडा पुलिस ने भारत 24 की एंकर शाज़िया निसार और एक दैनिक अखबार के डिजिटल विंग के एंकर आदर्श झा को गिरफ्तार किया है, इनके खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें रंगदारी, ब्लैकमेलिंग और धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं सूत्रों के अनुसार, दोनों पत्रकारों पर भारत 24 चैनल के शीर्ष अधिकारियों से 65 करोड़ की फिरौती मांगने और झूठे बलात्कार के आरोप लगाने की धमकी देने का आरोप है एफआईआर भारत 24 के प्रबंध निदेशक जगदीश चंद्रा, कंसल्टिंग एडिटर अनीता हाडा और एचआर प्रमुख अनु श्रीधर की शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई हैं। चैनल के सूत्रों ने बताया कि अन्य कर्मचारियों की शिकायतों के आधार पर और एफआईआर दर्ज हो सकती हैं पुलिस ने शाज़िया निसार के घर की तलाशी के दौरान 34 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। इसके बाद दोनों एंकरों को गौतम बुद्ध नगर की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक ने 'एक पेड़ माँ के नाम' वृक्षारोपण अभियान में लिया भाग

भोपाल। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ भावनात्मक जुड़ाव की भावना को प्रोत्साहित करते हुए, एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने आकाशवाणी परिसर, भोपाल में आयोजित 'एक पेड़ माँ के नाम' वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत एक पौधा रोपित किया। यह अभियान न केवल पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देता है, बल्कि मातृत्व की निस्वार्थ भावना को सम्मान देने का एक सुंदर प्रतीक भी है। इस अवसर पर प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा, अपनी माँ के नाम पर पौधा लगाना केवल उनके पोषणकारी प्रेम को सम्मान देने का कार्य नहीं, बल्कि प्रकृति को भी संजोने का एक संकल्प है। ऐसे अभियान हमें यह याद दिलाते हैं कि पर्यावरण की रक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा- भरा और स्वस्थ वातावरण छोड़ना है। एम्स भोपाल, प्रो. सिंह के नेतृत्व में, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता और सतत विकास से जुड़ी पहलों में सक्रिय सहभागिता निभाता आ रहा है, और आगे भी समाज और प्रकृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभाता रहेगा।

एम्स भोपाल के डेंटल विभाग के डॉ. अंशुल राय ने

सिंगापुर में तंबाकू सुपारी खाने के दुष्प्रभाव पर अपनी रिसर्च प्रेजेंट की

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह संकाय सदस्यों और छात्रों के बीच अकादमिक उत्कृष्टता और ज्ञान-साझाकरण की संस्कृति को सदैव बढ़ावा देते रहते हैं। प्रो. सिंह से प्रेरित होकर संकाय सदस्य विभन्न शोध कार्यों में असाधारण प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में, डॉ. अंशुल राय और उनकी टीम द्वारा की गई शोध को 80 देशों के 2000 से अधिक विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह शोध ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस -जिसमें मुँह खुलने में कठिनाई होती है–के उपचार पर केंद्रित है। यह अध्ययन 105 रोगियों पर किया गया, जिनमें से कई 10 वर्षों से अधिक समय से तंबाकू व सुपारी का सेवन कर रहे थे।

शोध में यह चिंताजनक तथ्य सामने आया कि लंबे समय तक सेवन करने वाले लोगों में ओएसएफ होने की संभावना अधिक होती है। इन रोगियों में से 8 को आगे चलकर मुँह का कैंसर भी हो गया। यह अध्ययन 9 वर्ष की उम्र से लेकर 70 वर्ष तक के ओएसएफ से पीड़ित मरीजों पर किया गया। विशेष रूप

से यह पाया गया कि पाउच (गुटखा/तंबाकू मिश्रित पदार्थ) का सेवन करने वालों में यह बीमारी अधिक पाई गई। 30 प्रतिशत महिलाएं भी इससे प्रभावित थीं। यहाँ तक कि 10 वर्ष से कम उम्र के 3 बच्चे भी इस बीमारी की चपेट में पाए गए। डॉ. अंशुल राय और उनकी टीम ने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग-अलग सर्जिकल प्रोटोकॉल विकसित किए, जिससे सटीक और प्रभावी इलाज संभव हो सका। ओएसएफ को एक प्री-मैलिग्नेंट कंडीशन माना जाता है, अतः सभी मरीजों का लंबे समय तक फॉलो-अप किया जाना जरूरी है। एम्स भोपाल के डेंटल विभाग ने मुँह खोलने हेतु एक नया फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल भी विकसित किया, जिसे मरीजों पर प्रयोग किया गया और इसके अत्यंत सकारात्मक परिणाम सामने आए। इस पद्धति से न केवल मुँह की गति में सुधार हुआ, बल्कि मरीजों को एक्सरसाइज करते समय दर्द भी नहीं हुआ। डॉ. राय ने यह भी बताया कि इलाज के दौरान उन्होंने कई नई तकनीकों का विकास किया, जिसके लिए उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से एक पेटेंट और 4 कॉपीराइट भी प्राप्त हुए हैं। इस उपलब्धि पर प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा– यह शोध कार्य न केवल चिकित्सा जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य के लिए भी एक अहम संदेश देती है। तंबाकू और सुपारी के सेवन से होने वाले खतरों को समझते हुए हमें जागरूकता और इलाज दोनों पर एक साथ काम करना होगा। डॉ. अंशुल राय और उनकी टीम ने जिस समर्पण और नवाचार के साथ इस चुनौतीपूर्ण विषय पर काम किया है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है।

नियम विरुद्ध स्वीकृति जारी करने पर सहायक यंत्री लालजी चौहान निलंबित

भोपाल(नप्र)। आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास श्री संकेत भोंडवे ने नगरपालिक निगम भोपाल में पदस्थ सहायक यंत्री लालजी चौहान को नियम विरुद्ध भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने के आरोप में निलंबित किया है। इस संबंध में अपर आयुक्त श्री कैलाश वानखेड़े ने आज आदेश जारी किये हैं। आयुक्त नगर निगम भोपाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार लालजी चौहान ने अपने कार्यकाल के दौरान नगर निवेशक के रूप में सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता बरती। प्रस्ताव में बताया गया कि 31 मार्च, 2025 से 2 मई, 2025 तक नगर निवेशक श्री अनूप गोयल के अर्जित अवकाश अवधि में लालजी चौहान को उनका कार्यभार सौंपा गया था। इस अवधि में लालजी चौहान ने नियम विरुद्ध स्वीकृतियाँ जारी कीं।

नगरीय आपदाओं की रोकथाम के लिये नियंत्रण कक्ष

भोपाल(नप्र)। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री संकेत भोंडवे के निर्देश पर वर्षा ऋतु में प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में जल-भराव, बाढ़, जर्जर भवनों के गिरने जैसी संभावित आपदाओं से निपटने के लिये भोपाल में राज्य स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। नियंत्रण कक्ष के संचालन एवं समन्वय के लिये एक विशेष दल का गठन किया गया है, जिसमें कार्यपालन यंत्री श्री उपदेश शर्मा, सहायक यंत्री श्री सुनील श्रीवास्तव सहित कुल 8 अधिकारी-कर्मचारी पदस्थ किये गये हैं। यह दल प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में जर्जर एवं क्षतिग्रस्त भवनों को चिन्हित करने और संबंधित नगरीय निकायों के बीच कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। राज्य स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष बाढ़ अथवा जल-भराव की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों के विस्थापन, मूलभूत सुविधाओं जैसी उपलब्धता के लिए समन्वय भी सुनिश्चित करेगा। नियंत्रण कक्ष मौसम कार्यालय से समन्वय कर पूर्व सूचना प्राप्त करेगा तथा संभावित रूप से प्रभावित नगरीय निकायों को अलर्ट भी जारी करेगा।

आदिवासी ग्राम उरदोन में एलपीजी गैस एवं प्रेसर कुकर वितरण किया गया

सुबह सवेरे सोहागपुर । सोहागपुर विकास खंड के आदिवासी ग्राम उरदौन में मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के एल.पी.जी गैस एवं प्रेशर कुकर वितरण समारोह कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह के आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डीएफओ मयंक सिंह

गुर्जर , अनुविभागीय अधिकारी अनिल जैन , सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एसडीओ अंकित जामोद , नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि यशवंत पटेल , नपा उपाध्यक्ष आकाश रघुवंशीइस , ब्लाक भाजपा मंडल अध्यक्ष अश्वनी सरोज , रेंजर दुर्गेशसिंह बिसेन , सीईओ संतोष अग्रवाल , डीई विघुत मंडल मुलाजदा जी के अलावा भाजपा जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा आदिवासी ग्रामीणों के साथ भारी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने अपने विस्तृत उद्बोधन में जनता-जनार्दन को एलपीजी गैस एवं प्रेसर कुकर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर नागरिकों एवं मातृशक्ति से इसका उपयोग करने का आव्हान किया।

कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास की सौगात

- 8 नये वर्किंग वूमेन हॉस्टल को मिली मंजूरी

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की कामकाजी महिलाओं के लिये वर्किंग वुमेन हॉस्टल की सौगात दी है। भारत सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट ऑफ स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के अंतर्गत 8 वर्किंग वूमेन हॉस्टल की स्वीकृति प्रदान की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि योजना अंतर्गत महिला श्रम बल भागीदारी दर (फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट) को बढ़ाने और महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में 8 वर्किंग वूमेन हॉस्टल की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से महिला बाल विकास विभाग द्वारा 4 वर्किंग वूमेन हॉस्टल और शेष 4 हॉस्टल औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा बनाये जायेंगे।

289 करोड़ रूपये की स्वीकृति हुई जारी: मंत्री सुश्री भूरिया ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा देवास, नर्मदापुरम और सिंगरौली में 100 सीटर तथा झाबुआ में 50 सीटर हॉस्टल बनाये जायेंगे। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा उज्जैन में 1554 सीटर, धार में 1776, रायसेन 776 और भिण्ड में 666 सीटर हॉस्टल का निर्माण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि वर्किंग वूमेन हॉस्टल के निर्माण के लिये 289.72 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 40.59 करोड़ की राशि महिला बाल विकास विभाग व्यय करेगी। वर्किंग वूमेन हॉस्टल का स्वामित्व राज्य सरकार के पास रहेगा और रख-रखाव का काम पीपीपी मोड पर किया जायेगा।

हॉस्टल में होंगी आधुनिक सुविधाएँ

वर्किंग वूमेन हॉस्टल में आधुनिक सुविधाओं सहित डे केयर सेंटर, जिम, इंडोर स्पोर्टस, लायब्रेरी, वाय-फाई, पर्याप्त पार्किंग, फूड कोर्ट और मनोरंजन गतिविधियां आदि उपलब्ध होंगी। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिससे कामकाजी महिलाओं का जीवन आसान होगा। विशेष रूप से जनजातीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में महिला श्रमिकों की आवास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह योजना क्रांतिकारी सिद्ध होगी।

अमृत हरित कार्यशाला 13 जून को रवीन्द्र भवन में

हरित क्षेत्र से जुड़े विषय-विशेषज्ञों के होंगे व्याख्यान

भोपाल (नप्र)। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा शुक्रवार 13 जून को प्रातः 8:30 बजे राजधानी भोपाल के रवीन्द्र भवन में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला अमृत हरित अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में हरित क्षेत्र के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों और पहलों का प्रसार करना है। कार्यशाला में मंत्रीगण, सांसद, विधायक, महापौर, निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जन-प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यशाला में प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रत्येक नगर निगम से 6, नगरपालिका परिषद से 4 और नगर परिषद से 2 प्रतिभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गयी है। कार्यशाला के दौरान कृषि और उद्यानिकी से संबंधित उत्पादों एवं यंत्रों की प्रदर्शनी के साथ ही नर्सरी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जायेगा। कार्यशाला में विभिन्न संस्थानों जैसे इफ्को एवं भारतीय प्रबंध संस्थान के विषय-विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जायेगी। कार्यशाला में स्थानीय वृक्ष प्रजातियों की विशेषताएँ एवं संरक्षण, जैव-विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, बगीचों के लिये तकनीक एवं उपकरण की आवश्यकताएँ, वृक्षारोपण और पौध-रोपण से संबंधित अधिनियमों का विश्लेषण तथा वृक्षारोपण उपरांत समुचित प्रबंधन विषय पर चर्चा की जायेगी।

हरित क्षेत्र बढ़ाने की रणनीतियाँ

कार्यशाला में दिव्यांग पार्क, होशंगाबाद एवं उज्जैन की सफलता की कहानियों को भी साझा किया जायेगा। इन कहानियों पर आधारित फिल्म का विशेष प्रस्तुतिकरण किया जायेगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण समस्त नगरीय निकायों में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किया जायेगा, जिससे राज्य के सभी निकाय इस अभियान से जुड़ सकें। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त श्री संकेत भोंडवे के निर्देशन में अपर आयुक्त श्री कैलाश वानखेड़े ने सभी नगरीय निकायों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये हैं। इसके साथ ही पौध-रोपण कार्य में संलग्न शासकीय और अशासकीय संगठनों के प्रतिनिधि भी कार्यशाला में भाग लेंगे।

विधायक कार्यालय में बैठक संम्पन्न

सुबह सवेरे सोहागपुर। संकल्प से सिद्धि अभियान के संदर्भ में सोहागपुर विधायक विजयपालसिंह के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी मंडल की महत्वपूर्ण बैठक किसान मोर्चा जिला मंत्री निखिलेश चतुर्वेदी के आतिथ्य में संपन्न हुई।इस बैठक में मोदी सरकार के सफल 11 वर्ष पूर्ण होने एवं भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में आगामी दिनों में आयोजित होने वाले 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस,23 जून बलिदान दिवस ,25 जून आपातकाल का काला अध्याय आदि कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा बनाई गई। इस अवसर पर की वक्ताओं ने इसी कार्यक्रमों को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए।बैठक के उपरांत भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया।इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि यशवंश पटेल, नपा उपाध्यक्ष आकाश रघुवंशी,मंडल अध्यक्ष अश्वनी सरोज ,वरिष्ठ वकील गोपाल माहेश्वरी,विजय छाबड़िया,राजेश शुक्ला, अनिल गहरैया,पार्षद आशीष विश्वकर्मा, पार्षद रवि शंकर उइके, पूर्व पार्षद राकेश चौरसिया,शंकर मालवीय, महामंत्री मिथलेश ठाकुर,ऋषभ गढ़वाल , प्रशांत मालवीय, शक्ति मेहरा,संध्या नागवंशी, संजय मेहरा, भगवान सिंह पटेल,डी सी साहू,अमर सिंह राजपूत,सुरेश कुशवाह,ब्रजेश राजपूत,देव सायलवार आदि भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इतिहास और सौंदर्य का संगम बन रहा है मध्यप्रदेश

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी और प्रेरक नेतृत्व में मध्यप्रदेश अपनी समृद्ध विरासत को सँजोते हुए देश और दुनिया के एक अनुपम पर्यटन राज्य के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री की परिकल्पना एक ऐसे मध्य प्रदेश की है जहाँ आधुनिकता और प्राचीनता का सामंजस्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दे। मध्यप्रदेश देश का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है, जहाँ धरती से निकलने वाले चमकदार और बेशकीमती रत्नों की तरह ही, यहाँ के रमणीय स्थल भी अपनी आभा बिखेरते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की प्रेरणा से प्रदेश का हर कोना इतिहास के अलग-अलग कालखंडों को दर्शाता एक विशाल संग्रहालय प्रतीत होता है। मध्यप्रदेश यानि भव्य किले, उत्कृष्ट नक्काशीदार मंदिर, प्राचीन शैल चित्र और अद्भुत स्मारक एक गौरवपूर्ण अतीत की जीवंत कहानी कहते हैं। मुख्यमंत्री का प्रयास है कि मध्यप्रदेश न केवल अपनी अमूल्य धरोहरों को संरक्षित करे, बल्कि उन्हें विश्व पटल पर एक अद्वितीय पहचान दिलाए, जिससे हर पर्यटक यहाँ आकर अपनी आत्मा को सुकून और ज्ञान से परिपूर्ण कर पाए।

मध्यप्रदेश जहाँ हर 100 किलोमीटर से भी कम की यात्रा में पुरातात्विक चमत्कारों और प्राचीन इमारतों के बीच आप अपने आपको पाते हैं। यहाँ का हर स्थान इतिहास के अलग-अलग काल को दर्शाने वाला एक विशाल संग्रहालय जैसा है। यहाँ मौजूद भव्य किले, नक्काशीदार मंदिर, ऐतिहासिक शैल चित्र और अद्भुत स्मारक एक गौरवपूर्ण इतिहास की कथा कहते हैं।

यूनेस्को की विश्व धरोहर

मध्यप्रदेश के खजुराहो की अलौकिक मूर्तियाँ, सांची का शांति स्तूप और भीमबेटका की ऐतिहासिक कलाकृतियाँ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थायी सूची में सम्मिलित हैं। इन धरोहरों के अतिरिक्त 18 अन्य पर्यटन स्थल भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल होने के साथ अब यात्रियों को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं।

मध्यप्रदेश अपने मूल मंत्र अतिथि देवो भव को गर्व से अपनाते हुए स्वच्छ, हरित और सुरक्षित स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। मध्यप्रदेश महिलाओं के अनुकूल यात्रा गंतव्य के रूप में भी विशेष स्थान हासिल कर चुका है, जो एकल और समूह यात्रियों के लिए समान रूप से आरामदायक और सुरक्षित अनुभव प्रदान करता है। यहाँ आने वाले यात्री प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की उन कहानियों के साक्षी बनेंगे, जो हजारों वर्षों पुराने इतिहास को बयां करती हैं और जो उनको दुनिया की हलचल से दूर सुकून के पलों का आनंद देने के लिए पर्याप्त हैं।

अतीत की कहानियों से रूबरू कराता ग्वालियर: कल्पना कीजिए एक ऐसे भव्य शहर की, जो देश के बाकी हिस्सों से आवागमन के लिए अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिसका राजसी किला सुनहरी धूप में किसी मोती की तरह चमकता है। यहाँ का हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, हर गली सदियों पहले के राजाओं, कवियों और यात्रियों के पदचिह्नों की गूँज से भरी हुई है। यह वही शहर है, जो गणित में शून्य के पहले लिखित प्रमाण का संरक्षक भी है। यह शहर है ग्वालियर, जो अपने शाही गलियारों में आपका स्वागत करने के लिए आतुर है।

मांडू - एक बीते युग के किस्से: प्रदेश में मौजूद एक अन्य ऐतिहासिक शहर, जहाँ छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भव्य स्मारक और नाजुक महल, शाही प्रेम कहानियों, चाँदनी रातों के गीतों और प्रेम-स्नेह के उन प्रेरणाओं को संजोए हुए हैं, जिन्होंने कवियों और सपने देखने वालों को प्रेरित किया। यही वह स्थान है, जहाँ ताजमहल निर्माण की कल्पना ने जन्म लिया। मनमोहक मांडू भी पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है।

चंदेरी - छिपे रहस्यों को उजागर करते स्थल: चंदेरी एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है, जहाँ ज़मीन के नीचे भी चमत्कार छिपे हुए हैं। यहाँ की प्राचीन बावड़ियाँ, जिनकी अद्भुत समरूपता और भूलभुलैया जैसी सीढ़ियाँ पर्यटकों को एक रहस्यमयी दुनिया में ले जाती हैं। यहां की बावड़ियां केवल कहानी ही नहीं सुनाती लोककथा भी कहती है जिनके अनुसार जब तक महासागरों में पानी रहेगा, तब तक ये बावड़ियाँ नहीं सूखेंगी। चंदेरी के किले और बावड़ियाँ पर्यटकों के इंतज़ार में हैं।

ठंडी फुहारों का आनंद - जबलपुर: एक रोमांचक अनुभव के लिए प्रसिद्ध शहर, जहाँ सफेद संगमरमर की ऊँची चट्टानों के बीच नाव की सवारी करते हुए पर्यटक सूरज की रोशनी में चमकते पानी और झरनों की गूँजती ध्वनि का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ नर्मदा नदी में चप्पुओं की लयबद्ध आवाज़ और ठंडी फुहारों का आनंद लेने के लिए पर्यटकों के स्वागत के लिए जबलपुर तैयार है।

धामनार - अखंड गुफाओं की कहानियां: एक ऐसा स्थान, जहाँ पत्थर की उत्कृष्ट कारीगरी और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ 5वीं-7वीं शताब्दी की कलात्मक और आध्यात्मिक उत्कृष्टता का प्रमाण स्वरूप पहाड़ी में उकेरी गई 51 से अधिक अखंड गुफाएँ मौजूद हैं। गुफाओं के भव्य दरवाजे, ऊँचे पत्थर के स्तंभ और जटिल मूर्तिकला शांति की अनुभूति कराते हैं। धामनार पर्यटकों को बीते युग की यात्रा पर ले जाने के लिए रोज ब रोज तैयार है।

बुरहानपुर - एक अद्भुत परंपरा का स्वाद: मध्य प्रदेश की यात्रा यहाँ के अद्वितीय स्वादों के अनुभव के बिना अधूरी है! यहाँ की गलियाँ मलाईदार मावा-जलेबी की सुगंध से महकती हैं। यहाँ दाल-चावल की एक साधारण थाली को भी पीली मिर्च के साथ परोसा जाता है और इसके साथ मिलने वाली जंगल के फूलों से बनी तीखी, सुगंधित महुआ चटनी इसका स्वाद और भी अनूठा बना देती है। बुरहानपुर पर्यटकों को ऐसे ही लज़ीज़ व्यंजनों से भरपूर दावत का हर समय अनुभव कराने के लिए तैयार है।

मंडला - राजाओं और रानियों की विरासत की दास्तान: एक ऐसा शहर, जो चार शताब्दियों तक राजसी रानियों, वीर राजाओं और शक्तिशाली साम्राज्यों का साक्षी रहा है। यहाँ तलवारों की टकराहट और दरबारी फुसफुसाहटें आज भी गलियों में गूँजती सी लगती हैं। मंडला अपने कम चर्चित, लेकिन अनूठे महलों के साथ, मध्यप्रदेश की शाही शान और ऐतिहासिक विरासत की झलक पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार है।

पर्यटन की अंतहीन कहानी

यह तो प्रदेश के महज कुछ रमणीय पर्यटक स्थलों की जानकारी है। इनके अलावा मध्यप्रदेश में कई पुरातात्विक और ऐतिहासिक अजूबे मौजूद हैं, जो सम्मोहक स्थलों, पौराणिक कथाओं और छिपे हुए चमत्कारों से भरे हुए हैं। ये सभी अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में सम्मिलित हैं और पर्यटकों के स्वागत के लिए तत्पर हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जहाँ हर शहर एक ऐतिहासिक कहानी को बयान करता है। यहाँ की हर विरासत एक रहस्य समेटे हुए है, और हर क्षण एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है।

7 माह बाद सोमवार से शुरू होगा जीएमसी मेन गेट

- मरीजों को नहीं लगाना पड़ेगा लंबा चक्कर, बूम बैरियर एक्टिव होने से बढ़ेगी सुरक्षा

भोपाल (नप्र)। गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) कैंपस का मेन गेट (रॉयल मार्केट की ओर) 16 जून को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद कॉलेज और हमीदिया अस्पताल कैंपस में आने के लिए लोगों को लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। यह गेट रिनोवेशन के लिए 15 नवंबर 2024 को बंद किया था। जीएमसी प्रबंधन ने तब कहा था कि 3 माह में गेट शुरू कर देंगे, पर 7 माह हो गए। मेन गेट बंद होने के कारण मरीजों को इमरजेंसी गेट और फतेहगढ़ वाले गेट से आना-जाना पड़ रहा है। मेन गेट से इंट्री बंद होने के कारण लोगों ने मेन गेट के पास स्थित मल्टीलेवल पार्किंग में वाहन खड़े करना भी बंद कर दिए है। जिससे पूरा कैंपस ही पार्किंग स्थल में बदल गया है। इस स्थिति में इमरजेंसी के दौरान फायर ब्रिगेड जैसे बड़े वाहनों के लिए कैंपस में चलना संभव नहीं है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार मरम्मत कार्य पूरा हो गया है। अब सिर्फ सपोर्ट में लगाई गई बांस-बल्लियों को हटाना और अंतिम चेकिंग बची है। यह काम इस सप्ताह पूरा हो जाएगा।

अभी यह स्थिति

वर्तमान में मरीजों, परिजनों, अस्पताल व मेडिकल स्टाफ के आने-जाने के लिए सिर्फ फतेहगढ़ वाला गेट चालू है। कलेक्ट्रेट की ओर से आने वाले लोगों को इस गेट तक पहुंचने के लिए कर्फ्यू वाली माता, मोती मस्जिद और सदर मंजिल से होकर आना पड़ता है। यह करीब 1.5 किलोमीटर का चक्कर है। इस रोड पर पीक अवर्स में 15 हजार से ज्यादा वाहन एक घंटे में गुजरते हैं, ऐसे में यहां हमेशा जाम की स्थिति भी बनी रहती है। जिससे काफी समय बर्बाद होता है।

बाहरी लोगों पर रोक नहीं

मालूम हो कि अस्पताल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक नहीं है। कुछ समय पहले जूडा ने इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन को पत्र भी लिखा था। इस पत्र में बताया था कि कुछ बाहरी लोग अस्पताल में भर्ती मरीजों को इलाज पूरा होने से पहले ही डिस्चार्ज करवाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके अलावा मरीजों को आईपीडी में भर्ती होने से पहले ही उन्हें निजी अस्पताल में बेहतर इलाज का आश्वासन देने लगते हैं। जूडा ने संदेह जताया था कि निजी अस्पतालों के दलाल हमीदिया अस्पताल कैंपस में सक्रिय हैं।

बूम बैरियर एक्टिव होने से बढ़ेगी सुरक्षा

मेन गेट शुरू होने के बाद, जीएमसी कैंपस और हमीदिया अस्पताल में आने-जाने के 3 गेट होंगे। इनमें से एक इमरजेंसी गेट सिर्फ एम्बुलेंस के लिए आरक्षित है। वहीं, रॉयल मार्केट वाले गेट और फतेहगढ़ वाले गेट पर लगे बूम बैरियर भी एक्टिव हो जाएंगे। जिससे कैंपस में आने वाले हर वाहन की जानकारी और फोटो सर्वर में दर्ज होगी। अभी जो बाहरी लोग कैंपस में माहौल खराब करने का काम करते हैं, उनकी पहचान आसान हो जाएगी। जिससे इस तरह की असामाजिक गतिविधियों के रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने में मदद मिलेगी।

बिजली खपत कम करेंगे तो बिल भी कम ही आएगा, रीडिंग में भी कोई गड़बड़ी नहीं हो रही

- घरेलू स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं ने बताए फायदे

भोपाल (नप्र)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की पहल पर भोपाल सहित पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र के 16 जिलों में घरेलू स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। भोपाल शहर वृत्त में लगभग तीन माह पहले लगाए जा चुके स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से जब बातचीत की तो अनेक सकारात्मक पहलू सामने आए। अधिकतर स्मार्टमीटर उपभोक्ताओं ने फायदा होने की बात कही है। मकान नंबर 23, देवीनगर कॉलोनी करोंद भोपाल के उपभोक्ता श्री महेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि उनके यहां तीन महीने पहले स्मार्ट मीटर लगा था। शुरू में उन्हें डर था की कहीं स्मार्ट मीटर से बिल तो अधिक नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही अगले महीने बिल आया तो देखा कि कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं आई। बल्कि अब तो ऐप के माध्यम से अपने घर के बिजली उपयोग को भी नियंत्रित करना सीख गए हैं, क्योंकि जो उपकरण हम अधिक समय चलाते थे, उन पर नियंत्रण करने से बिल में अब कमी आई है। इसी तरह करोंद के ही देवकी नगर की उपभोक्ता श्रीमती देव कुमारी ने बताया कि स्मार्ट मीटर से रीडिंग लेने में कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि अब तो अपने आप रीडिंग हो रही है और सटीक रीडिंग हो रही है। अब तो न कोई रीडिंग लेने आता है, बल्कि अपने आप दूरसंचार प्रणाली से रीडिंग हो रही है और निर्धारित तिथि को सही रीडिंग का बिल मोबाइल पर दिया जा रहा है। एक अन्य स्मार्ट मीटर उपभोक्ता मकान नंबर 87, गांधीनगर निवासी श्री शेरू रजक ने बताया कि अब हमें बिजली की खपत की हर पंद्रह मिनट में जानकारी मिल रही है। इससे अंदाजा लगाना आसान हो गया कि हम किस समय कितनी बिजली की खपत करते हैं। इससे एक तो बिजली की बचत करने में आसानी हो रही है, दूसरी बात यह कि बिल में पूरी पारदर्शिता आ गई है, क्योंकि रीडिंग में गलती होने की अब जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। मकान नंबर 53, एकतापुरी निवासी अमित सेमल ने बताया कि वे जिस किराए के मकान में रहते हैं, वहां स्मार्ट मीटर लगा है। हमें डर था कि कहीं बिल अधिक आया तो कैसे भरेंगे। लेकिन नया मीटर लगने के बाद पहले ही महीने में हमने देखा कि सब्सिडी घटाकर बिल तो 82 रूपये ही आया है। इसके बाद लगातार तीन माह हो गए 100 रुपये से कम ही बिल आ रहा है, क्योंकि हमारी बिजली खपत कम है। इसलिए हमारे लिए तो यह मीटर फायदेमंद है।

घरेलू स्मार्ट मीटर के फायदे

- ऊर्जा की खपत को ट्रैक करने और ऊर्जा की बचत करने में मदद करता है।
- बिजली की खपत को सटीक रूप से मापता है, जिससे बिल में कोई गलती नहीं होती।
- एप के जरिए मोबाइल पर रियल-टाइम डेटा देखकर ऊर्जा की खपत को नियंत्रित कर सकते हैं।
- ऊर्जा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है, ताकि ऊर्जा की खपत को बेहतर बना सकते हैं।

एक ही थाने में 5 साल से पदस्थ पुलिसकर्मी हटेंगे

पीएचक्यू ने भोपाल, इंदौर कमिश्नर, रेल एसपी को दिए निर्देश, 16 जून से होंगे तबादले

भोपाल (नप्र)। पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) ने पूरे मध्यप्रदेश के पुलिस अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जो पुलिसकर्मी (आरक्षक से उपनिरीक्षक तक) किसी एक थाने में 4 साल या उससे ज्यादा समय से तैनात हैं, उनका तबादला 16 जून तक जरूर कर दिया जाए। यह आदेश भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर, जबलपुर और भोपाल के रेल पुलिस अधीक्षक और प्रदेश के सभी जिलों के अफसरों को दिया गया है। साथ ही तबादले की जानकारी पीएचक्यू को भी भेजनी होगी।

यह निर्देश स्पेशल डीजी (प्रशासन) आदर्श कटियार ने जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि थानों में लंबे समय से तैनात पुलिसकर्मियों को हटाना जरूरी है ताकि कामकाज पारदर्शी और जनता के हित में बना रहे। समय-समय पर तबादला होने से काम में भी बदलाव आता है और पुलिस के खिलाफ शिकायतें भी कम होती हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा पहले भी इसको लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं लेकिन कई जिलों में इस पर अमल नहीं किया गया है। इसलिए इसके निर्देश दोबारा जारी किए जा रहे हैं।

तबादले के नियम क्या हैं?

- किसी भी पुलिसकर्मी को एक ही थाने में एक पद पर 4 या 5 साल से ज्यादा नहीं रखा जाएगा।
- तबादला होने के बाद उसी थाने में फिर से उसी पद पर पोस्टिंग नहीं मिलेगी।
- अगर किसी को फिर उसी थाने में लाना हो, तो कम से कम 3 साल का गैप होना जरूरी है।
- एक ही पुलिस क्षेत्र (जैसे एसडीओपी या सीएसपी के अंतर्गत आने वाले थाने) में अलग-अलग पदों पर कुल मिलाकर 10 साल से ज्यादा पोस्टिंग नहीं हो सकती। इसमें अटैचमेंट की पोस्टिंग भी गिनी जाएगी।

खाटूश्याम से किडनैप 3 साल का रक्षम मथुरा से मिला

6 जून को भोपाल के बच्चे का हुआ था अपहरण, आरोपी प्रधान को देकर भागा

भोपाल (नप्र)। सीकर के खाटूश्याम मंदिर से किडनैप 3 साल के रक्षम को पुलिस ने मथुरा के स्यारहा गांव से बरामद कर लिया है। मंदिर परिसर से 6 जून को भोपाल के रहने वाले बच्चे का अपहरण हो गया था। मासूम अपनी मां और नानी के साथ दर्शन के लिए आया था। जयपुर में परिवार को मिला एक युवक उसे लेकर गायब हो गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी सतीश पुत्र मानसिंह बच्चे को अपने गांव के प्रधान को देकर भाग गया। प्रधान ने पुलिस को बच्चे को लेकर जानकारी दी। जब बच्चे को अपने मां-बाप को सौंपा गया तो वो एकदम ठीक था। पुलिस की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वो मोबाइल से खेलता दिखा।

किडनैपर ट्रेन से बच्चे को गांव लेकर पहुंचा

भोपाल के रहने वाले रक्षम को सीकर पुलिस ने उसके मां-बाप को सौंप दिया। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि किडनैपर सतीश सिंह बच्चे को सीकर मथुरा ट्रेन से लेकर पहुंचा था। यहां से वो अपने गांव स्यारहा पहुंचा। किडनैप बच्चे की जानकारी मिलने पर गांव के प्रधान ने लोकल

पुलिस को जानकारी दी थी किडनैपर का पूरा परिवार गांव में ही है। पुलिस के अनुसार आरोपी अनमैरिड है और गांव में ही मजदूरी का काम करता है। आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं, बच्चे की किडनैपिंग क्यों की गई इसको लेकर भी जांच की जा रही है।

कैसे हुआ बच्चे का किडनैप

बच्चे की मां ललिता जाटव ने बताया कि 6 जून को वे भोपाल से अपनी मां आशा अहिरवार और बेटे के साथ जयपुर पहुंची थी। स्टेशन के बाहर उन्हें एक 25 से 30 साल की उम्र का युवक मिला था। उसने बताया कि वो भी खाटूश्याम दर्शन के लिए जा रहा है। वो हर एकादशी पर बाबा के यहां जाता है। इसके बाद वे सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंचे। यहां से वे साथ ही रींगस फिर खाटू पहुंचे।रास्ते में उसने बताया कि वो वृंदावन (यूपी) का रहने वाला है। उसने अपना नाम नहीं बताया था।

मंदिर में बोला था- दीदी बच्चा मुझे दे दो

ललिता जाटव ने बताया कि- मंदिर में एकादशी के कारण काफी भीड़ थी। तबीयत खराब होने के कारण बेटा रो रहा था। कई बार उल्टी भी कर चुका था। तब युवक बोला- दीदी आप परेशान हो रहे हो। बच्चे को आप मुझे दे दो।युवक बेटे को गोद में लेकर दुलार करते हुए लाइन में चल रहा था। मैंने अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाया था। उसने कहा था-आप दोनों दर्शन करके आ जाओ।आपके आने के बाद मैं दर्शन कर लूंगा। भीड़ और बच्चे की तबीयत को देखते हुए विश्वास कर लिया। बेटे को उसकी गोद में देकर दर्शन करने गई। वापस लौटी तो बेटा नहीं मिला और न ही युवक।

जल गंगा संवर्धन अभियान

प्रदेश में पेयजल स्रोतों की सफाई के साथ जन जागरूकता अभियान भी जारी

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से जारी है। अभियान के दौरान ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाकर सुखद भविष्य के बारे में बताया जा रहा है। अभियान के दौरान जिले भर में प्राचीन बावड़ियों को चिन्हित कर उनकी मरम्मत और सफाई कार्य हाथ में लिया गया है। प्रदेश में लगातार जल यात्राएं निकाली जा रही हैं। वर्षा के मौसम को देखते हुए व्यापक पौधरोपण की कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है।

उत्कृष्ट कार्य करने वालों किया सम्मानित: सिंगरौली जिले में नौगढ़ में जन अभियान परिषद द्वारा हनुमान मंदिर के पास बावड़ी में साफ-सफाई वृक्षारोपण व दीप प्रज्ज्वलित कर बावड़ी उत्सव मनाया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली नवांकुर संस्था को विधायक श्री राम निवास शाह और कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर शुक्ला ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान में पानी की बचत को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जल यात्रा का आयोजन किया गया। इसी के साथ जल स्रोतों की साफ-सफाई जनभागीदारी से की गई। जल चौपाल में जन सामान्य को नदी-तालाबों के किनारों पर निरंतर सफाई करते रहने की समझाइश दी गई। सामूहिक भागीदारी में महिला कार्यकर्ताओं के माध्यम से अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी करने के लिये जन जागरूकता अभियान चलाया गया।

मुख्यमंत्री ने प्रख्यात साहित्यकार प्रो. हाशमी के निधन पर दुःख व्यक्त किया

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रतलाम निवासी प्रख्यात साहित्यकार प्रो. अजहर हाशमी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रो. अजहर हाशमी का कल रतलाम में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि साहित्य की विभिन्न विधाओं में श्री हाशमी ने निरंतर कार्य किया। वे विभिन्न धर्म ग्रंथों के अध्ययन में भी रुचि रखते थे। उनके निधन से मध्यप्रदेश ने एक शीर्ष और प्रतिष्ठित साहित्यकार खो दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रो. हाशमी की आत्मा की शांति और उनके शोकाकुल परिजन को यह दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया बिस्मिल जी का पुण्य स्मरण

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मां भारती की परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जीवन समर्पित करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, श्रद्धेय रामप्रसाद 'बिस्मिल' की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि काकोरी केस सहित विभिन्न प्रयासों से बिस्मिल जी ने दमनकारी हुकूमत की जड़ें हिला दीं और असंख्य देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता सेनानी बिस्मिल जी का योगदान स्मरणीय रहेगा।

उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की अध्यक्षता में म.प्र.राज्य स्तर राष्ट्रीय सेवा योजना, पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र चयन प्रक्रिया की बैठक हुई।

दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह कांग्रेस से निष्कासित

पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायतों के चलते 6 साल के लिए किया बाहर

भोपाल(नप्र)। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य तारिक अनवर ने लक्ष्मण सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने की शिकायतों के चलते 6 साल के लिए निष्कासित किया है।

लक्ष्मण सिंह ने राहुल और राबर्ट वाड्रा पर दिया था बयान

लक्ष्मण सिंह ने 24 अप्रैल को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं। लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी को भी सोच समझकर बात करने की नसीहत देते हुए कहा था कि पार्टी को मुझे निकालना हो तो आज निकाल दे। हमारी पार्टी के नेता सोच समझकर बोले, नहीं तो उन्हें चुनाव में परिणाम भुगतना पड़ेंगे।

कांग्रेस ने नोटिस जारी कर मांगा था जवाब: लक्ष्मण सिंह के बयान पर कांग्रेस ने संज्ञान लेते हुए 9 मई को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पार्टी की अनुशासन समिति के सदस्य सचिव तारिक अनवर ने उनसे 10 दिन में जवाब मांगा था। जवाब संतोषजनक नहीं होने के चलते उनके निष्कासन की अनुशंसा की गई थी। आलाकमान की ओर से मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस की अनुशासन समिति के सदस्य तारिक अनवर ने 6 साल के लिए निष्कासित करने का आदेश जारी किया है।

विधायक और सांसद रह चुके हैं लक्ष्मण सिंह

मध्यप्रदेश की सियासत में राघौगढ़ रियासत का दबदबा कहा जाता है। इस रियासत से दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब राज्यसभा सदस्य हैं। उनके बेटे जयवर्धन सिंह राघौगढ़ से विधायक हैं। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा से विधायक रहे हैं। इससे पहले वे सांसद भी रहे, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि लक्ष्मण सिंह को उतनी तवज्जो नहीं मिली जितना दिग्विजय सिंह के परिवार को मिली है। 2018 में जब 15 साल बाद मप्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो लक्ष्मण सिंह को उम्मीद थी कि वरिष्ठता के आधार पर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन उनकी जगह दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को मंत्री बनाया गया। लक्ष्मण सिंह इससे आहत हुए। उन्होंने उस वक्त खुल कर विरोध नहीं जताया मगर गाहे-बगाहे अपनी पीड़ा जाहिर करते रहे।

बीजेपी विधायक बोले- सच कहना बगावत तो हम भी बागी

लक्ष्मण सिंह के मामले पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने कहा- लक्ष्मण सिंह मेरे वर्षों पुराने मित्र हैं। जब उनके भाई साहब मुख्यमंत्री थे तब से आज तक लक्ष्मण सिंह और हम मित्र हैं। बेबाकी से बोलते हैं। आज की तारीख में वे जो सवाल उठा रहे हैं। वो समयानुकूल हैं। इन प्रश्नों का जवाब कांग्रेस को आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा।अगर जवाब नहीं देंगे। तो जनता और कार्यकर्ता उन्हें इतना घेरेंगे कि वो लक्ष्मण सिंह का नाम लेकर पानी पिएंगे। मैं भाई लक्ष्मण सिंह के भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं और ये भी कहता हूं कि आप अपनी लाइन को मत छोड़िएगा। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। आप और हम इसी लाइन पर चलते रहेंगे। आज तक मुझे ऐसा लगा नहीं कि कभी उन्होंने बीजेपी में आने की मंशा जाहिर की। व्यक्तिगत मित्रता के नाते भी कह रहा हूं कि वो बीजेपी में नहीं आएंगे।

वीडी बोले- कांग्रेस को सत्य का आईना दिखाते रहते हैं: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने देवास में कहा- यह कांग्रेस संगठन का निर्णय है। इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नही है। लेकिन लक्ष्मण सिंह कभी-कभी कांग्रेस को सत्य का आईना दिखाते रहते हैं, तो कांग्रेस में सत्य का आईना दिखाने वालों का क्या हाल होता है। मुझे लगता है कि लोग जानते ही हैं और शायद वही लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ है।

बीजेपी प्रवक्ता बोले- ये कांग्रेस के सृजन से विसर्जन की शुरुआत

लक्ष्मण सिंह के निष्कासन पर बीजेपी के प्रवक्ता डॉ. हितेष वाजपेई ने कहा- इस प्रकार से कांग्रेस के सृजन से विसर्जन की यात्रा शुरू होती है। खेल को समझिए, जीतू पटवारी ने संगठन की रचना पहले नहीं की। उन्होंने राहुल जी का फायदा उठाकर सबसे पहले अपने कट्टर विरोधी दिग्विजय सिंह के भाई को निपटा दिया। ये करके प्रदेश में एक मैसेज भी दे दिया। अब वो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। जिससे कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में उनका वर्चस्व कायम रहे। अभी तो शुरुआत हुई है आगे - आगे देखिए होता है क्या जीतू भाई ने अपनी चालें चलना शुरु कर दिया है। जिसका पहला खामियाजा दिग्विजय गुट को देखने को मिला है।